युपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी, बेटियों ने लहराया परचम

टॉप 3 में दो लड़िकयां, शक्ति दुबे बनीं टॉपर

मंगलवार को युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग (यपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए। इसमें शक्ति दुबे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं, हर्षिता गोयल और डोंगरे अर्चित पराग को द्वितीय एवं तृतीय रैंक मिली है। शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक (विज्ञान स्नातक) किया है। आयोग दारा जारी एक बयान में कहा गया कि दुबे ने राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की। एमएस विश्ववद्यालय बड़ौदा से बीकॉम स्नातक हर्षिता गोयल ने राजनीति विज्ञान और

अंतरराष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के

रूप में लिया और परीक्षा उत्तीर्ण की।

: 79,595.59

: 24,167.25

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

O BRIEF NEWS

मणिपुर में चार उग्रवादी

111.00

हर्षिता गोयल को द्वितीय व अर्चित पराग को मिला तृतीय स्थान, झारखंड के छात्रों को भी कामयाबी

शीर्ष 25 अभ्यर्थियों में 11 महिलाएं व 14 पुरुष शामिल 🕨 16 जून 2024 को हुई प्रारंभिक परीक्षा में 14,627 उम्मीदवारों का हुआ था

🕨 सितंबर 2024 में आयोजित मुख्य परीक्षा में 2845 उम्मीदवारों का हुआ था चयन साक्षात्कार के बाद 1009 का हुआ चयन, 725 पुरुष व 284 महिलाएं शामिल







जमशेदपुर के ऋत्विक को मिला ११५वां स्थान

कर रहे थे। इससे पूर्व 2023 में लोयोला स्कूल के पूर्व छात्र ऋत्विक ऋत्विक का चयन आईपीएस में को सिविल सेवा परीक्षा में 115वां रैंक मिला है। ऋत्विक ने अपनी हुआ था। वे फिलहाल सरदार

पदाधिकारी हैं, जबिक मां प्रियंका वर्मा प्रतियोगी परीक्षा की गाइड का प्रकाशन करती हैं। ऋत्विक के छोटे भाई वेदांत मेहता ने भी यपीएससी



बोकारो के राजकुमार को मिला ५५७वां स्थान

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बोकारो जिले के चास प्रखंड के तियाड़ा गांव के राजकुमार महतो ने 557 वीं रैंक हासिल की है। लेकिन जुझारू परिवार से आते हैं। उनके पिता रामपद महतो कभी कपडा सिलते थे. लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को बेहतर शिक्षा देने का सपना नहीं छोड़ा। राजकमार की प्रारंभिक से लेकर प्लस टू तक की पढ़ाई चास स्थित जीजीपीएस स्कूल से हुई।

जम्मू-कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला 27 लोगों की गई जान



जम्मु-कश्मीर में 2019 के पुलवामा

अटैक के बाद सबसे बडा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाड और ओडिशा के हैं। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौट रहे हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इसमें कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। भारत में मौजूद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी घटना पर दुख जताया है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2.45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने धर्म पूछ कर लोगों को मारा। यूपी से आए शुभम द्विवेदी से उनका नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम की दो महीने पहले ही शादी हुई थी। वो हनीमून पर यहां आया था। आतंकी पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो y आतंकियों ने दूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी नेपाल-यूएई के 2 दूरिस्ट मारे गए

मरने वालों में से 18 के नाम आए सामने

। . मनुज नाथ (कर्नाटक) २ . शिवम मोगा (कर्नाटक) ३. लेफ्टिनेंट विंजय नरवाल (हरियाणा) ४. शुभम द्विवेदी (यूपी) 5. दिलीप डेसले (महाराष्ट्र) 6. अतुल मोहने (महाराष्ट्र) 7. सैयद हुसैन शाह (अनंतनाग) 8. अंधकेरी उधवानी कुमार (यूएई) १२. संजय लेले १३ . हिम्मत कलाथय १४. प्रशांत कुमार १५. मनीष रंजन (हैदराबाद) १६. रामचन्द्रन १७. शलिंदर कल्पिया १८. दिनेश

तैयबा ने ली है। प्रशासन ने आतंकी हमले में एक मौत की बात कही थी, लेकिन करीब 4 घंटे बाद एजेंसी ने 26 मौतों की जानकारी दी। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में 27 लोगों के मरने का दावा किया गया है। घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पहलगाम में हमले

गए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-वाले इलाके को घेर लिया है। गह मंत्री पहंचे जम्म-कश्मीर. सीएम. एलजी के साथ की मीटिंग

घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैटक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमत्रा उमर अब्दुल्ला तथा लाफ्टनट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

जांच के लिए पहलगाम पहंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर घटना की निंदा की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाइ का भरासा दिया है। घटना स जुडे कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

एनआईए की टीम बुधवार को हमले की

हेमंत ने टेस्ला को गीगा फैक्ट्री लगाने का दिया प्रस्ताव झारखंड को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की ओर बढ़े कदम

मख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों स्पेन और स्वीडन के दौरे पर हैं, जहां वे झारखंड में निवेश आकर्षित करने की दिशा में सिक्रय प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक, खेल, चिकित्सा, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना है। बार्सिलोना में आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकों में झारखंड सरकार को कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है झारखंड में गीगा



मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना टेस्ला (चेकोस्लोवाकिया) के सीईओ और सह-संस्थापक डुशान लिचार्डस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में एक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

प्रारंभिक पढ़ाई लोयोला से करने के वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आईपीएर

र-झारखंड के 15 ढिकानों पर ईडी रेड, मिले कई दस्तावेज

बोकारो वन भूमि घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

गिरफ्तार. हथियार बरामद मंगलवार को बोकारो वन भूमि IMPHAL: मणिपुर पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से प्रीपाक (प्रो) के चार घोटाले की जांच में प्रवर्तन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इंफाल निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो ईस्ट जिले के सागोलमांग थाना क्षेत्र के गई है। बोकारो में हुए 100 एकड़ अंतर्गत नगखापत एडवेंचर खारोक इलाके से ज्यादा के वन भूमि घोटाले से प्रीपाक (प्रो) के तीन उग्रवादियों को मामले में ईडी ने छापेमारी की। गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार ईडी ने झारखंड और बिहार के को बताया कि गिरफ्तार किए गए कुल 15 ठिकानों पर छापा मारा। आरोपितों की पहचान नोंगथोम्बम माइनगौ टीम ने बोकारो वन विभाग के सिंह (33), नोंगथोम्बम मोहन सिंह (45) दफ्तर, सीओ कार्यालय और रांची और केशम साना लैमा उर्फ तमफासना उर्फ लिंगजेल (40) के रूप में हुई है। के लालपुर स्थित हरिओम टावर, पुलिस के अनुसार, ये तीनों आरोपित कांके और हटिया समेत कई इंफाल ईस्ट जिले के खुंद्रकपम क्षेत्र इलाकों में छापेमारी की। रांची में स्थित नाओरेम बीराहारी कॉलेज के पास यह कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से दो व्यक्तियों के फिरौती के लिए के दफ्तरों और उससे जुड़े लोगों अपहरण की घटना में शामिल थे। पुलिस के आवास पर की गई। ईडी के टीम ने अपहत दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित अधिकारियों ने दस्तावेजों की रिहा कराया। गिरफ्तारी के दौरान जांच के साथ पछताछ भी की। यह आरोपितों के कब्जे से एक .32 बोर की पिस्तौल, एक मैगजीन के साथ जिसमें रेड बोकारो में सामने आए वन पांच राउंड गोलियां लोड थीं, छह मोबाइल भमि घोटाले को लेकर की गई है। हैंडसेट, एक काले रंग की कमर बेल्ट इस दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण और दो दोपहिया वाहन बरामद किए गए। दस्तावेज भी बरामद किए।

रांची के लालपुर स्थित हरिओम टावर, कांके व हटिया सहित कई इलाकों में छापेमारी बोकारो वन विभाग के दफ्तर, सीओ कार्यालय में दबिश, अधिकारियों से भी पूछताछ



फर्जी दस्तावेज के आधार पर भू-माफिया ने बेच दी ११७ एकड़ जमीन

बता दें कि इससे पूर्व झारखंड सीआईडी ने बोकारों के सेक्टर 12 थाना में दर्ज कांड़ संख्या 32/2024 को टेकओवर कर अपनी जांच शुरू की थी। जमीन

माफिया को लेकर बोकारो वन प्रमंडल के प्रभारी वनपाल–सह– शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के बाद पता चला कि बोकारो में

अधिकारी और भू-माफियाओं ने मिलकर ११७ एकंड़ जमीन फर्जी अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है।

फाइनेंशियल पावर देने का विभाग ने दिसंबर में ही दिया था आदेश

ोगों के आवास पर की गई है यह कार्रवाड़ इससे पूर्व सीआईडी

रितुडीह और सेक्टर ३, उकरीद स्थित रैयत इजहार हसैन व अख्तर के आवास पर छापा

ने सेक्टर 12 थाना में दर्ज कांड को टेकओवर कर शुरू की थी जांच

चास अंचल कार्यालय पहुंची टीम

बोकारो के जिला वन पदाधिकारी के कार्यालय और बोकारो में सीओ कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी चली। चास अंचल कार्यालय में भी के मामले में झारखंड पलिस की अपराध अनसंधान विभाग

(सीआइडी) भी जांच कर रही है। वन भूमि घोटाले का मामला वर्ष २०२२ का है। जनवरी २०२५ में बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी इसकी शिकायत की थी।

बोकारो एनकाउंटर : फायरिंग में जख्मी नक्सली सहित दो को पुलिस ने किया गिरफ्तार



PHOTON NEWS BOKARO: बोकारो जिले में सोमवार को हुए

एनकाउंटर में एक करोड़ के इनामी नक्सली विवेक सहित आठ नक्सलियों को मार गिराने के बाद एक और बड़ी सफलता सुरक्षाबलों के हाथ लगी है। मंगलवार को सुरक्षाबलों ने एक महिला सहित दो नक्सलियों को दबोचा है। गिरफ्तार दो नक्सलियों में से एक घायल अवस्था में इलाज करवाते पकड़ा गया है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने महिला नक्सली अनीता और नक्सल कैडर दयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को हुए एनकाउंटर में कई नक्सलियों के घायल होने की बात सामने आई थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास कई किलोमीटर तक सघन सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति के गोली से घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने उस घर को घेर लिया, जहां पर घायल

व्यक्ति इलाज करवा रहा था।

नक्सिलयों में एक महिला भी शामिल अब खुलेंगे कई राज

अरेस्ट किए गए

- **रार्च अभियान के** दौरान सूरक्षा हालों को मिली कामयाबी
- 🗕 घायल दयानंद के पास से बरामद किए गए दो हथियार

अंदर जाने पर नक्सली कैडर दयानंद घायल अवस्था में पकड़ा गया। दयानंद को दो गोलियां लगी थीं। उसके पास से दो हथियार भी बरामद किए गए हैं। दयानंद का इलाज अब पुलिस की सुरक्षा में करवाया जा रहा है। सोमवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच जब मुठभेड़ शुरू हुई तो आगे की पंक्ति में गोली चला रहीं दो महिला नक्सली तालो दी और रंजू मांझी मौके पर ही मारी गईं।

स्वास्थ्य विभाग का आदेश नहीं मान रहे सिविल सर्जन

VIVEK SHARMA @ RANCHI: डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने लगाया आरोप, लिखे तीन पत्र, चौथा लेटर लिखने की तैयारी

स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन जिले

के प्रमुख होते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर व कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी उन्हीं की देखरेख में संचालित होते है। लेकिन, रांची सदर हॉस्पिटल के मामले में वह स्वास्थ्य विभाग का आदेश नहीं मान रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग के आदेश के बावजूद डिप्टी सुपिरिंटेडेंट

(डीएस) को वह 4 महीने से फाइनेंशियल पावर नहीं दे रहे है। इससे डीएस को काम करने में परेशानी आ रही है। यह आरोप डीएस ने सिविल सर्जन पर लगाया है।

के दमोह जिले में नोहटा थाना अंतर्गत

ग्राम सिमरी के पास महादेव घाट पर

होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में

आठ लोगों की मौत हो गई जबकि पांच

लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें

कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके

पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद

से घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस

ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के

शुरू कर दी है। मृतकों में तीन बच्चे

और पांच महिलाएं शामिल हैं। पुलिस

के अनुसार जबलपुर के भीटा फूलर

गांव का परिवार बांदकपुर से जागेश्वर

धाम के दर्शन करने के बाद वापस लौट

रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे

बनवार चौकी क्षेत्र में महादेव घाट के

पास यह हादसा हो गया। बोलेरो में 15

लोग सवार थे। हादसे में छह लोगों की

मौके पर ही मौत हो गई थी।

लिए भेज दिया है और मामले की जांच

एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित

बोलेरो में सवार एक ही परिवार के

दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती

चार माह पहले ही दिया गया था आदेश

डीएस डॉ. बिमलेश सिंह ने बताया कि दिसंबर में ही स्वास्थ्य विभाग ने फाइनेंशियल पावर देने का आदेश दिया था। लेकिन, उन्होंने आजतक पावर हैंडओवर नहीं किया है। इसके लिए तीन बार

सिविल सर्जन को पत्र लिखकर सदर हॉस्पिटल से जड़े अहम फाइनेंशियल पावर हैंडओवर देने की मांग की है। अब चौथी बार सिविल सर्जन को पत्र लिखने की तैयारी में है।

क्या कहते हैं सिविल सर्जन इस मामले में सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार

का कहना है कि डीएस को चार अकाउंट पिछले साल दिसंबर महीने में ही हैंडओवर किए गए हैं। सदर अस्पताल की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक खाता है। दूसरा एनएचएम का पूरा खाता जिसमें जेएसएसके, जेएसवाई ऑदि शामिल हैं। करोडों रुपये इस खाते से जडे हैं। तीसरा हेमेटोलॉजी से संबंधित सभी खर्च डीएस को ही करने हैं। हेमेटोलॉजी विभाग का खर्च 5 करोड़ से कम नहीं है। चौथा ब्लड बैंक खाता और पांचवां डीएस द्वारा अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी का खाता। पत्र में जो भी लिखा गया था, उसका पूरी तरह से पालन किया गया है।

खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के ८ की मौत DAMOH: मंगलवार को मध्य प्रदेश

सिस्टम की कमजोरी अधिकार समूहों की ओर से किए गए सर्वे में हुआ खुलासा

दिव्यांगों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK

साल २०४७ तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और आत्मनिर्भरता के सभी पहलुओं को मजबूत करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में व्यापक विजन के साथ काम को धरातल पर उतरने को लगातार तरजीह दी है। जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक

गया है। इसके लिए हर स्तर पर कड़ी मेहनत की योजना- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पूरी तरह अनजान हैं।

राष्ट्रीय दिव्यांगजन नेटवर्क की अहम बैठक में सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर की गई चर्चा

34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 5 हजार से अधिक दिव्यांगों से की गई बातचीत

पहुंचाने के लिए स्ट्रांग सिस्टम को डेवलप किया

जा रही है। इसके बावजूद, अगर देश के दिव्यांगों तक सरकारी योजनाओं के ठीक से नहीं पहुंचने की स्थिति है, तो यह सिस्टम की कमजोरी है। इसका मतलब साफ है कि पीएम मोदी के व्यापक विजन को साकार करने के लिए और कड़ी मेहनत की जरूरत है। हाल में अधिकार समूहों द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे में यह जानकारी सामने आई है कि भारत में 82 प्रतिशत दिव्यांगों के पास किसी भी प्रकार का बीमा नहीं है। इतना ही नहीं 42 फीसद दिव्यांगजन सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य

आयुष्मान फॉर <u>ऑल</u> पीएम मोढ़ी के व्यापक

देश के 82% दिव्यांगो प्रकार का कोई बीमा

योजना से ४२%

दिव्यांग पूरी तरह

राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केंद्र द्वारा आयुष्मान फॉर ऑल अभियान के तहत सर्वेक्षण किया गया. जिसमें ३४ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5 हजार से अधिक दिव्यांगों

विजन को साकार करने के लिए और कड़ी

28 प्रतिशत दिव्यांगों ने ही किया है आवेदन

से बातचीत की गई। इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ पदान करना है। इसके बावजद केवल २८ फीसद दिव्यांग ही इसके लिए आवेदन कर पाए हैं।

राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार प्रकाश डाला कि जहां आयष्मान भारत 70 वर्ष से

स्वास्थ्य बीमा जीवनयापन की जरूरत

संवर्धन केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने बताया है कि ये आंकडे केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि उन लोगों का प्रतिनिधत्व करते हैं,जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवा से वंचित हैं। स्वास्थ्य बीमा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनके जीवनयापन की जरूरत है। अरमान अली ने सरकार के नियमों पर सवाल उटाया। उन्होंने इस बात पर

अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिना शर्त कवरेज प्रदान करता है, वहीं विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, विकलांगता और गरीबी एक दष्वक्र का हिस्सा हैं। हम केवल योजनाओं की मांग नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिनिधित्व और नीतिगत बदलावों की मांग कर रहे हैं।

Wednesday, 23 April 2025

BRIEF NEWS

खूंटी के कांग्रेस नेता फिलमोन हेरेंज का निधन KHUNTI: खंटी जिला आदिवासी कांग्रेस के संरक्षक फिलमोन हेरेंज



जुलियूस भेंगरा, मगरीता खेस, ईन्दुआन्ना हस्सा, सुन्दरमनी हंस, शांता खाखा, हेलेन तिडू, सुषमा भेंगरा, फुलचंद टूटी, रोबा गुड़िया, अनिता नाग सहित अन्य ने शोक व्यक्त किया है।

सोन नदी से लिफ्ट कर बांध व तालाबों तक पहुंचेगा पानी

PALAMU : पलाम् जिले के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत मोकहर कला पंचायत के किसानों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी योजना



की शुरूआत हो गई है। मंगलवार से शुरू हुई इस योजना के तहत 'पलामू पाइप लाइन इरिगेशन पैकेज फेज-2' के तहत सोन नदी से पानी मखिया नाजमा खातन और

समाजसेवी नवाजिश खान ने जानकारी दी कि इस योजना के पूर्ण होते ही इलाके के सभी प्रमख जल स्रोतों को पर्याप्त जलापर्ति मिलने लगेगी. जिससे किसानों की सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी और क्षेत्र का भूमिगत जलस्तर भी बढ़ेगा। योजना की जिम्मेदारी संभाल रही गुजरात की लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट इंजीनियर अभिषेक सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की सिक्रयता और सरकार की पहल के चलते यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

मालवाहक ट्रक घर में घुसा, मकान क्षतिग्रस्त



LOHARDAGA : नेशनल हाईवे 39 कुडू - रांची मुख्य पथ पर कुडू थाना क्षेत्र के नावटोली गांव के समीप सोमवार देर रात्रि एक बड़ा हादसा होते - होते टल गया। जब कुडू की तरफ से धान लोड कर रांची जा रहा मालवाहक ट्रक नेशनल हाईवे 39 में सड़क किनारे बनाएं गए नाली पर लगा स्लैब को तोड़ते हुए मकान में प्रवेश कर पलट गया। घटना में चालक तथा खलासी को मामुली चोट लगी। लेकिन मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कुडू पुलिस को मंगलवार को मामले की जानकारी दी गई है। बताया जाता है कि गढ़वा जिले के एक निजी गोदाम से धान लोड कर मालवाहक ट्रक रांची जा रहा था। सोमवार देर रात कुडू थाना से दो किलोमीटर दूर नावाटोली गांव के समीप ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया तथा ट्रक नाली को ध्वस्त करते हुए सड़क किनारे बने प्रवीण खाखा तथा सुमन खाखा के मकान में प्रवेश करने के बाद पलट गया। प्रवीण खाखा तथा सुमन खाखा ने बताया कि रात मे खाना खाने के बाद सोने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच दूसरे कमरे में तेज आवाज के साथ एक ट्रक दीवार को तोड़ते हुए मकान के आधे हिस्से में

अलग-अलग घटनाओं में 24 घंटे में तीन की हुई मौत

पलामू जिले के पांडू, कंडा व नावाबाजार में हुईं सड़क दुर्घटना

पलामु जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी। मरने वालों में एक महिला और दो पुरूष शामिल हैं। पांडू थाना क्षेत्र के रतनाग में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मारकर 62 साल की महिला की जान ले ली, वहीं मोहम्मदगंज-सतबहिनी रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 345/13 भीम चुल्हा टनल के पास रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक का शव

वहीं एनएच 98 डालटनगंज-औरंगाबाद मुख्य पथ पर नावाबाजार थाना क्षेत्र के कंडा में कार-ट्रक के बीच हुई टक्कर में



कंडा में घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त कार

• फोटोन न्यूज

जख्मी कार सवार युवक की इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मौत हो गयी। महिला और युवक का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अज्ञात युवक के शव

पहचान के लिए सुरक्षित रखा

जिले के नावाबजार थाना क्षेत्र के कंडा में कार-ट्रक के टक्कर से जख्मी दूसरे युवक छतरपुर के खोड़ी के मनीष यादव ने भी दम तोड दिया है। छतरपर रामगढ के

दुसरे युवक की शव का पोस्टमार्टम उपायुक्त के निर्देश पर एमआरएमसीएच में किया गया। सत्येन्द्र यादव के शव का मंगलवार को दाह संस्कार हुआ। उल्लेखनीय है कि छतरपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी गांव से गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के रक्सी गांव बारात गए पांच लोग ब्रेजा कार से लौट रहे थे। कंडा में पहुंचने पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से कार में जोरदार टक्कर हो गई थी जिससे पांचो सवार जख्मी हो गए थे। हादसे में जख्मी एक और की हालत चिंताजनक बनी

जिले के पांड्र प्रखंड के रतनाग

सत्येन्द्र यादव की मौत हुई थी। मोटरसाइकिल चालक ने एक 62 साल की महिला की जान ले ली। मत महिला की पहचान कलावती देवी पति नंदू विश्वकर्मा के रूप में की गई। पांडू-छतरपुर मुख्य पथ पर रतनाग में कलावती देवी अपने पुराने घर की तरफ सड़क पार कर रही थी। इसी क्रम में हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे गांव के हीं जितेंद्र चौधरी ने जोरदार धक्का मारा, जिससे कलावती देवी जख्मी होकर गिरी एवं मौके पर ही उसकी मौत हो गईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पांडू पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लिया

एवं मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज

60 दिनों में निष्पादित



पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों के समीक्षा एसपी अजय कुमार ने की। मंगलवार को एसपी कार्यालय में उन्होंने जिले के तमाम थाना प्रभारी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान महिला लैंगिक अपराध एवं पोक्सो एक्ट से संबंधित लंबित कांड़ो की विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। साथ ही कांडों का अनुसंधान त्वरित गति से करते हुये ससमय निष्पादन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया एसपी अजय कुमार के द्वारा लंबित कांडों को लेकर अनसंधानकर्ता. थान प्रभारी, ओपी प्रभारी, इंस्पेक्टर और सीडीपीओ को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। एसपी अजय कुमार ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन 60 दिनों के अंदर करना है। साथ ही पीएसओ पोर्टल पर समय पर अपलोड भी किया जाना है। एसडीपीओ और इंस्पेक्टर को हर सप्ताह लैंगिक अपराध और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा करनी होगी।

जमशेदपुर की डॉ. इशिका सिंह बनी आईएएस प्रथम प्रयास में ही हासिल किया २०६वां स्थान



अपने परिवार के साथ डॉ. इशिका सिंह

PHOTON NEWS JSR:

शहर में पली-बढ़ी डॉ. इशिका सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की है। उन्हें 206वां रैंक मिला इससे पहले इशिका एमबीबीएस की पढ़ाई कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूरी कर चुकी हैं। • फोटोन न्यूज

इशिका ने प्लस टू की पढ़ाई हुबली स्थित केंद्रीय विद्यालय से की थी। इशिका के पिता राजेश कुमार सिंह का टेल्को स्थित खड़ंगाझार में आवास है। ननिहाल प्रकाशनगर, टेल्को में है। इशिका के पिता हुबली में सफल उद्योगपित के रूप में जाने जाते हैं। सिंह टाटा हिताची में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इशिका

लिपिक के पुत्र सौरम को मिली 49वीं रैंक

DUMKA : युपीएससी परीक्षा में दुमका के 28 वर्षीय सौरभ सिन्हा ने 49वां रैंक हासिल किया है । रसिकपुर के मध्यमवर्गीय परिवार से ने वाले सौरभ के पिता प्रियव्रत सिन्हा जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में बडा बाबू हैं। सौरभ ने नर्सरी से इंटर तक की पढाई दुमका में की। ग्रीन माउंट एकेडमी से मैट्रिक तक की पढाई बिना किसी ट्यूशन के की। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी सौरभ ने कभी हार नहीं मानी। स्वाध्याय के बल पर पढ़ाई की। पढ़ाई के प्रति जुनून था। वर्ष 2021 में उसने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक और एमटेक किया। इसके बाद किसी कंपनी में नौकरी नहीं की। सौरभ वर्तमान में नारायणा विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रोफेसर है। गिरिडीह जिले के राजधनवार के बीजेपी नेता पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह के पुत्र दिव्यांशु शांडिल्य ने यूपीएससी निकाल लिया है। ज्ञात हो कि लक्ष्मण सिंह के दामाद इंद्रजीत महथा सरायकेला व पश्चिमी सिंहभूम में एसपी रह चुके हैं। संयोगवश लक्ष्मण सिंह भी सरायकेला-खरसावां जिले के एसपी थे।

रामगढ़ के वैभव भी बने आईएएस

RAMGARH: रामगढ़ जिला अंतर्गत सीसीएल कुजू क्षेत्र के एसओ पीएंडपी वीरेश कुमार के पुत्र वैभव कुमार भी आईएएस बन गए हैं।

बोकारो के सौरभ राजेंद्र बने आईएएस

BOKARO : चिन्मय विद्यालय, बोकारो के पूर्व छात्र सौरभ राजेंद्र भी आईएएस बने हैं। सौरभ को 199वां रैंक हासिल हुआ है।

की माता किरण सिंह हुबली एवं छोटा भाई ऋषित भी स्थित कॉलेज में प्राध्यापिका हैं।

गुमशुदा मूक-बधिर बालक को परिजनों को किया गया सुपुर्द



परिजनों के साथ मूक-बधिर बालक

• फोटोन न्यूज

RAMGARH: रामगढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से एक मुक-बधिर बालक को उसके परिजनों से मिलाया गया। मंगलवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बालक को परिजनों को सौंपा। नौ सितंबर 2024 को वात्सल्य धाम बालगृह के हाउस फादर को सूचना मिली थी कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक कोठार ओवर ब्रिज के पास खड़ा है। हाउस फादर द्वारा संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखभाल दुखहरण महतो को इसकी सूचना दी गई। इसके पश्चात चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने तत्काल बच्चे को वात्सल्य धाम बालगृह पहुंचाया गया। 10 सितंबर 2024 को मुकबधिर बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बालक को बाल गृह में आश्रय दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से बच्चे के गमशदगी की फोटो यक्त तस्वीर अखबार में प्रकाशित की गई।

खदान में लगी आग का कारण जानने पहुंचे सांसद

भुचुंगडीह की खदान में लगी थी आग, कोयला तस्करी पर भी हुई चर्चा

रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रो में कोयले की तस्करी धडल्ले से जारी हैं। कोयला तस्करी पर रोक लगाने में जिला प्रशासन विफल साबित हो रहा हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भुचुंगडीह के अवैध खदान में आग लगना है। ये बातें हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल ने भुचुंगड़ीह में मंगलवार को कही । हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल अवैध खदान में लगी आग का निरीक्षण करने भूचुंगडीह गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भुचुंगडीह गांव में हजारों लोग रहते हैं। दो दिन पूर्व भुचुंगडीह के अवैध खदान में आग लग गयी हैं। जो दुःखद

घटना हैं। आग कैसे लगी और



लोगों से बात करते सांसद मनीष जायसवाल

• फोटोन न्यूज

को बंद किया जा सके। साथ ही कोयला तस्करों पर कानूनी कार्रवाई हो सके। उन्होंने

भी कहा की जहां आग लगी है वह कोयला की तस्करी कर रहे हैं। इसपर उच्चस्तरीय जांच होनी क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है और वहां अवैध माइनिंग का कार्य चाहिए। ताकि ऐसे अवैध खदानों में वन विभाग चुप्पी साधे हुए है । सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राज्य की सरकार हर मोर्चे में फेल है। कोयला तस्करों के बल्ले जिला प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने यह बल्ले हैं। रात के अंधेरे में कोयला

की तस्करी हो रही है। पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। सांसद ने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलने पर वे भुचुंगड़ीह पहुंचे हैं। आखिर अवैध खदान किसके संरक्षण में चल रहा हैं और भुचुंगडीह में भीषण आग के पीछे दोषी कौन हैं? इस दौरान सांसद के आगमन पर जिला प्रशासन के और से जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक. सीसीएल रजरप्पा के जीएम कल्याण प्रसाद, वन विभाग के रेंजर और अंचल अधिकारी दीपक मिंज ,रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय वहां पहुंचे चुके थे ।सभी पदाधिकारियों को सांसद ने त्वरित करवाई का निर्देश देते हुए कहा कि सभी अवैध मुहानों को अविलंब बंद कर

भू-माफिया के खिलाफ

RAMGARH: रामगढ शहर में भ माफियाओं के खिलाफ आवेदन देना समाज से भी पंकज महतो को भारी पड़ गया। उसे जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पंकज पंकज महतो ने कहा कि मंगलवार को जब वह अपने एक दोस्त कौलेश्वर कुशवाहा के घर पर गए थे, उसी समय भू माफिया कृष्णा प्रसाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि जान से मारने की नीयत से उन पर हमला भी किया गया। लेकिन वे बाल-बाल बच गए। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि सिदो- कान्हू मैदान के पीछे वाले ८ एकड़ ३५ डिसमिल जो मां काली मसना के बारे उपायुक्त और अन्य जगह आवेदन दिए हो, जिसका अंजाम बुरा होगा। सारा जमीन ८ एकड़ 35 डी मैंने और राजबल्लभ अग्रवाल , निवासी- रामगढ़ ने मिलकर बेचा है। राजबल्लभ अग्रवाल पर राधाकष्ण मट की 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन के फजीर्वाडे सीआईडी जांच कर रही है। पंकज महतो ने कहा कि रामगढ़ पुलिस

आरोपियों पर कार्रवाई करें।

आवेदन देना समाजसेवी को पड़ा भारी, मिली धमकी

इस पूरे मामले की जांच करें और

सीमेंट कामगार यूनियन ने संघर्ष में मांगा लोगों का साथ

सीमेंट कामगार यूनियन की जनरल जोजोबेड़ा चेचिस यार्ड में हुई। निगमानंद पाल की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में जोजोबेड़ा स्थित न्यूवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड में उत्पादन, मेंटनेंस, इलेक्ट्रिकल, पंप कंप्रेसर, हाउस कीपिंग, गार्डेन और कैंटीन, एमएचएस स्टोर आदि में काम करने वाले मजदर सीमेंट वेज बोर्ड के साथ सेवा शर्त पाने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में 2008 से लड़ते आ रहे हैं। इसकी सुनवाई झारखंड उच्च

न्यायालय में 4 अप्रैल को हुई। मजदूरों ने इस लड़ाई में तन, मन, धन से सहयोग करने का फैसला किया। इसके साथ ही यह भी कहा कि आज लगभग 16 वर्ष बीत



जोजोबेड़ा में नारेबाजी करते सीमेंट कामगार

• फोटोन न्यूज

चके हैं, न्यायालय से न्याय की गुहार लगाते हुए। दर्जनों मजदुर सेवानिवृत्त भी हो गए। सीमेंट कामगार यूनियन ने गत माह कंपनी प्रबंधन को 15 सूत्री मांग पत्र सौपा था। यह समझौता एक जनवरी से लंबित है। बैठक में मजदुरों ने यह भी तय किया है कि इस बार मजदूर दिवस भव्य तरीके से

मनाया जाएगा। संगठन के महासचिव सह एटक झारखंड के सचिव अंबज कमार ठाकुर ने कहा कि मजदूर एकता बनाए रखें। इस दौरान सत्येंद्र सिंह, शंभू सिंह, ज्वाला प्रसाद, अजय सिंह, राम सिंह, रेणु मुर्मू, सबिता सोरेन, रंजन पांडे आदि सहित कई

विधायक सरयू राय ने कहा- नदियों पर डैम बनाने से पर्यावरण पर पड़ रहा प्रतिकूल असर

आईआईटी (आईएसएम) व युगांतर भारती के बीच हुआ एमओयू

सूचित करने को कहा।

PHOTON NEWS DHANBAD: झारखंड में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में संयुक्त रूप से प्रयास करने के लिए स्वयंसेवी संस्था युगांतर भारती और आईआईटी-आईएसएम धनबाद के बीच एमओयू हुआ। युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण और आईआईटी-आईएसएम धनबाद की तरफ से प्रोफेसर अंशुमाली ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस ओमओयू का मकसद जैव विविधता के संरक्षण, शैक्षणिक जानकारी व रुचि की सामग्रियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान, संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम, पर्यावरण मुद्दों पर सेमिनार, कार्यशाला, जागरूकता कार्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित करना व स्वरोजगार

उत्पन्न करना, शैक्षणिक साहित्य

का आदान-प्रदान, संयुक्त परामर्श



कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक सरयू राय

रिसर्च के बाद ही गुण-अवगुण का पता चलता है : प्रो. एसके गुप्ता

आईआईटी-आईएसएम, धनबाद के डीन एस .के .गुप्ता ने कहा कि ज्ञान का विश्लेषण ही विज्ञान है। पहले किसी भी चीज की खोज होती है, उसके बाद उसपर रिसर्च होता है। रिसर्च के बाद ही उसका गुण–अवगुण हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, जब हमें जीवाश्म ईंधन का विकल्प ढूंढना होगा। हमें नवीकरणीय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा जैसे प्राकृतिक विकल्पों की जोर मुड़ना होगा। तभी हम पृथ्वी को गर्म होने से बचा पाएंगे और यह धरा हमारे रहने लायक रहेगी।

इस दौरान जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने कहा है कि निदयों को बांधा नहीं

सेवाएं, अनुसंधान गतिविधियों और जाना चाहिए। उन्हें बांधने से, उन प्रकाशन संबंधित कार्य करना है। पर डैम बनाने से पर्यावरण पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है। अब भारत समेत दुनिया भर में नदियों को बांधने पर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। वह आईआईटी

धनबाद कभी था सुव्यवस्थित शहर

विशिष्ट अतिथि तथा भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत संजय रंजन सिंह ने आईआईटी-आईएसएम धनबाद की 100वीं वर्षगांठ पर संस्थान के सभी शिक्षकों और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि धनबाद एक सुव्यवस्थित शहर था। पहले यहां अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। वायु प्रदूषण नाममात्र की थी। ओपन माइनिंग के कारण ओवर बर्डन हो गया है। यह धनबाद के सीने पर बहुत बड़ा बोझ है। धनबाद का वातावरण अत्यधिक विषैला हो

(आईएसएम), युगांतर भारती,

मेल-हब के संयुक्त तत्वावधान में

आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य

अतिथि बोल रहे थे।

(आईएसएम), धनबाद में विश्व पृथ्वी दिवस पर आईआईटी

नौकरी ही रह गया आज की शिक्षा का ध्येय पर्यावरणविद डा. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि आजकल हमारे

शिक्षा का ध्येय केवल नौकरी है। नौकरी तो सभी करते है, पर काम कोई-कोई ही करता है और जो काम करता है उसी की पहचान होती है। पर्यावरण के क्षेत्र में इस देश को काम करने वालों की

दामोदर बचाओ आंदोलन के धनबाद जिला संयोजक अरुण राय ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन के लिए धरोहर है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। स्वागत भाषण आईआईटी (आईएसएम) के पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. आलोक सिन्हा ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सुरेश पांडियन ने किया। मंच संचालन मेल-हब की डॉ. मेघा त्यागी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आईआईटी (आईएसएम), धनबाद के पर्यावरण विभाग, मेल-हब के शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी सक्रिय रहे।

सरयू राय ने कहा कि नदियों पर जैसे संस्थान को प्रकृति के डैम बनाने के दुष्परिणाम धीरे-धीरे पैथोलॉजिकल टेस्टिंग सेंटर की अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। तरह बताया, जहां मानवीय और यही वजह है कि अब इनका गतिविधियों से पृथ्वी और पर्यावरण विरोध दुनिया भर में हो रहा है। पर पड़ने वाले प्रभावों का पता उन्होंने आईआईटी, आईएसएम चलता है। राय ने कहा कि आज

है। यह इंसान ही है, जिसने प्रकृति का अपने हित के लिए दोहन किया और उसकी हालत खराब की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आईआईटी खडगपुर के प्रो. अशोक कुमार गुप्ता ने पीपीटी के माध्यम से 'ट्रांसफॉर्मिंग एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन इंडियाः एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एप्रोच' विषय पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत व्याख्यान दिया। संगोष्ठी का विषय प्रवेश करते हुए आईआईटी (आईएसएम) के प्रो अंशुमाली ने कहा कि लैंड पॉलिसी सभी पॉलिसियों की जननी है, क्योंकि सभी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता होती है। आजकल सरकार भी भूमि अधिग्रहण के बदले रैयतों को काफी बढ़िया मुआवजा दे रही है।

पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा

मानवीय गतिविधियों से ही हो रहा

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर सजेगा दीवान

मजदूर उपस्थित थे।



JAMSHEDPUR : सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत को समर्पित कार्यक्रम शहर में पूरे साल भर तक होंगे। इसे लेकर संस्था वीर खालसा सेवा दल से जुड़े लोगों ने मंगलवार को बैठक की और इसकी रूपरेखा तैयार की। तय हुआ कि कार्यक्रम की शुरूआत साकची एवं जुगसलाई में कीर्तन दरबार से होगी। 25 अप्रैल की सुबह व शाम का दीवान साकची गुरुद्वारा तथा 26 अप्रैल को सुबह व शाम का दीवान जुगसलाई स्टेशन रोड गुरुद्वारा में सजेगा। इसमें भाई रविंदर सिंह युके वाले और हेड ग्रंथी सिंह साहिब बचितर सिंह शहादत का इतिहास और कथा से संगत को निहाल करेंगे।











CITY



O BRIEF NEWS टेरर फंडिंग मामला : महेश अग्रवाल की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

RANCHI: चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पावर के तत्कालीन महाप्रबंधक महेश अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सनाया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को महेश अग्रवाल की

याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में नौ अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। महेश अग्रवाल ने अपने खिलाफ किए गए चार्जफ्रेम और खारिज किए गए डिस्चार्ज पिटीशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआईए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। एनआईए ने टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या 2/2016 को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था। अनुसंधान के बाद एनआईए ने मामले में 17 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र

रिम्स में ७५ साल की महिला की हुई ओपेन हार्ट सर्जरी

एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में एक 75 साल की

दाखिल किया था।



सीएफ एंड्रयूज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस

यह बीमारी अत्यधिक जटिल होती

है, क्योंकि वॉल्व में जमा कैल्शियम

को निकालने और नए वॉल्व को

प्रत्यारोपित करते समय हार्ट ब्लॉक

का खतरा रहता है।

सीएफ एंड्रयूज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनिमा बोस और सचिव दीप्तिमान बोस उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत में शिक्षिका शिवांगी बनर्जी, रोमी वर्मा, भवानी कमारी और अंतरा विश्वास ने पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार साझा किए। सचिव ने प्लास्टिक और प्रदुषण के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने पौधारोपण में उत्साहपर्वक भाग लिया। पर्यावरण जागरूकता के लिए रंगीन चार्ट और पोस्टर भी बनाए। प्रधानाध्यापिका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास में उनके योगदान की सराहना की।

झारखंड में लंबित नहीं मतदाता सूची में सुधार से जुड़ी कोई अपील

झारखंड में मतदाता सची से संबंधित मामलों में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार, वर्तमान समय में मतदाता सची में किसी भी प्रकार के सुधार या संशोधन से जुड़ी कोई अपील जिला निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) कार्यालय के समक्ष लंबित नहीं है। यह राज्य में मतदाता सूची की गुणवत्ता और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को दशार्ता है।

बीएलओ करते हैं सत्यापन : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों

- >> निर्वाचन आयोग की और से जारी रिपोर्ट में किया गया खुलासा
- ≫ इससे स्पष्ट होता है कि वोटर लिस्ट की गुणवत्ता व निर्वाचन प्रक्रिया में कायम रही पारदर्शिता
- **»** बीएलओ की मेहनत, एजेंट्स की सक्रियता व नागरिकों की जागरूकता का है परिणाम

की नियुक्ति की जाती है, जो



मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त घर जाकर सत्यापन का कार्य करता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान घर- है। साथ ही प्रत्येक राजनीतिक दल

सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता

द्वारा लिया जाता है।

राज्य में कुल २ करोड़

राज्य में कुल २ करोड़ ६२ लाख

से अधिक पंजीकत मतदाता हैं और

29 हजार से अधिक बीएलओ इस

प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। मतदाता

सुची में नाम जोड़ने, हटाने या

संशोधन के लिए क्रमश : फॉर्म 6,

7 और 8 का उपयोग किया जाता

है। बीएलओ द्वारा आवेदन का

सत्यापन करने के बाद अंतिम

निर्णय निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी

६२ लाख वोटर

मतदाता कर सकते हैं अपील

लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(क) के तहत यदि कोई व्यक्ति ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह डीईओ के पास प्रथम अपील और फिर सीईओ के पास द्वितीय अपील कर सकता है। हालांकि राज्य में वर्तमान में ऐसी एक भी अपील लंबित नहीं है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची में दर्ज जानकारी से मतदाता पूरी तरह संतुष्ट हैं। निर्वाचन विभाग का मानना है कि यह सब बीएलओ की मेहनत, एजेंटस की सक्रियता और नागरिकों की जागरूकता का परिणाम है। यह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है।

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेट ने कांके डैम की दुर्दशा पर जताई नाराजगी, बोले-

रांची की लाइफलाइन को नहीं होने देंगे बर्बाद

PHOTON NEWS RANCHI: मंगलवार को केंद्रीय रक्षा राज्य

मंत्री संजय सेठ ने कांके डैम का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति को देखकर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान रांची नगर निगम के अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने डैम की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह डैम रांची की आधी आबादी को पानी मुहैया कराता है और इसकी यह हालत शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डैम से उठती दुर्गंध के कारण किनारे खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल आवास तक इसी डैम का पानी जाता है। फिर भी यहां की हालत यह है तो बाकी जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रांची की लाइफलाइन को युं बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा।

लगा है जलकंभी का अंबार डैम के चारों ओर जलकंभी और गंदगी का अंबार लगा है, जिससे पानी की गुणवत्ता बुरी

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आवास तक इसी डैम का जाता है पानी



कांके डैम का निरीक्षण करते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ

वाटर टीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश

केंद्रीय मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने रातू रोड और कांके रोड की ओर से आने वाले गंदे नाले के पानी को रोंकने और वहां वॉटर टीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, जल संसाधन विभाग, मत्स्य पालन विभाग और पर्यटन विभाग को मिलकर डैम के संरक्षण के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांके डैम सिर्फ एक जलाशय नहीं, बल्कि रांची की जीवनरेखा है। इसका संरक्षण सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस डैम को पुनर्जीवित करने और इसके लिए केंद्र से हर संभव मदद दिलाने के लिए तैयार हूं।

तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने में गुणवत्तापूर्ण केमिकल का डैम कभी मॉर्निंग वॉकर्स और पाथवे है, न छायादार पेड़, न

प्रयोग नहीं होने से साफ पानी कहा कि वाटर फिल्टर प्लांट की आपूर्ति बाधित हो रही है।

विरोध स्वाभाविक है। परिवारों के लिए आकर्षण का

विरोध स्वाभाविक

यह निरीक्षण एक बार फिर

दर्शाता है कि विकास और

पर्यावरण संतुलन की जरूरत

है, और अगर योजनाएं जन

भावनाओं और पर्यावरणीय

आवश्यकताओं को नजरअंदाज

करके बनाई जाएं, तो उनका

केंद्र था. लेकिन आज वहां न

यहां कैसे मनाएंगे छट

उन्होंने निरीक्षण के दौरान छट महापर्व को लेकर चिंता जताई। मंत्री ने कहा कि छट आने में सिर्फ 5-6 महीने बाकी हैं और डैम की पूरी सीढियां तोड़ दी गई हैं। छट पर लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं। ऐसे में यह सवाल उढता है कि पर्व कैसे मनाया जाएगा? उन्होंने विकास के नाम पर डैम को पूरी तरह कंक्रीट से ढंकने की योजनाओं को भी गलत ठहराया और इसे पर्यावरण विरोधी करार दिया।

लोगों ने भी बताई अपनी समस्याएं

निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने भी मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। मंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि कांके डैम को फिर से साफ– सूथरा, हरा-भरा और उपयोगी बनाने के लिए जल्द ही टोस कदम उटाए जाएंगे।

बच्चों के झले और न ही बुजुर्गों के लिए बैठने की कोई

झारखंड की नींव खोद रहे बाल् माफिया : बाबूलाल



का प्रतीक है। मरांडी ने के प्रदेश अध्यक्ष और लिखा कि मैंने पूर्व में भी नेता प्रतिपक्ष बाबुलाल मरांडी सिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे ने झारखंड में अवैध बालू खनन अवैध बालू कारोबार को सरकार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में लाया था लेकिन पर निशाना साधा है। मरांडी ने अब ऐसा प्रतीत होता है कि मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिल्ली के राढ़ नदी पर बने एक पुल का हवाला देते हुए कहा कि यह पुल अब कभी भी गिर सकता है, क्योंकि वह बालू माफियाओं के निशाने पर है। उन्होंने आरोप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है लगाते हुए लिखा कि हेमंत सोरेन जबिक जमीनी स्तर पर सिल्ली के पोषित बालू तस्कर सिर्फ पुल से रांची के बीच पड़ने वाले सभी की बुनियाद नहीं खोद रहे, बल्कि थानों की पुलिस पूरी ईमानदारी से विकास की संभावनाएं, युवाओं बालू ढोने वाले वाहनों से वसूली का भविष्य और सरकार की नींव कर राशि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रही है। खोद रहे हैं। भष्टाचार और अवैध खनन की भेंट चढ़ चुका सिल्ली उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए में राढ नदी पर बना पल कभी भी भरभरा कर ध्वस्त हो सकता है। साधी गयी, तो यह इस लूट में

सरकार के प्रयासों से महिलाओं की बढ रही पहचान : शिल्पी नेहा तिर्की

किष मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चान्हो और मांडर प्रखंड कार्यालय परिसर में महिलाओं के बीच सिलाई मशीन, आपदा राहत कोष, सड़क दुर्घटना के आश्रितों को मुआवजा, ओलावृष्टि से नुकसान का मुआवजे का वितरण लाभुकों में किया। मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के कथन को याद रखने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था समाज का विकास उस समाज में महिलाओं की स्थिति से परखा जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राज्य सरकार के प्रयासों से सशक्त हो रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएं



कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व अन्य

पर हैं। मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग के सौजन्य से सिलाई मशीन के वितरण करने से महिलाएं सामूहिकता के साथ स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं की पहचान रोजगार के क्षेत्र में स्थापित हो रही है। महिलाएं बेहतर टेनिंग कर सहकारी समितियों से जुड़कर

• फोटोन न्यूज अपना भविष्य खद संवार सकती हैं। समाज में कई मौके ऐसे आते हैं जब महिलाएं सामृहिक रूप से काम करते हुए पैसा अर्जित करती हैं। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण सरकार की योजनाओं से अब भी अनभिज्ञ हैं। लाभुकों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उनके बैंक खाते में आपदा राहत कोष का पैसा आ रहा है।

अजीम प्रेमजी विवि में पर कार्यक्रम शुरू

RANCHI: अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से आदिवासी समुदायों का स्वास्थ्य और जमीन पर काम करने के अनुभव एवं सीख नामक कार्यक्रम की शुरूआत मंगलवार को की गयी। यह कार्यक्रम दो दिनों तक चलेगा। पिछले कछ दशकों में आदिवासियों के स्वास्थ्य और सेहत में काफी सुधार देखा गया है, लेकिन फिर भी दूसरे समुदायों के मकाबले आदिवासी समदायों का स्वास्थ्य कई मानकों पर बहत पीछे है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकडे बताते हैं कि आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य की स्थिति बेहद नाजुक है। इन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी सीमित मात्रा में ही पहुंच पाई हैं।

मीटिंग में संविधान बचाओ अभियान के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

जर्जर पुल झारखंड की अंदर से

मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राज उपस्थित थे। इस दौरान केंद्र सरकार पर संविधान और जन अधिकारों पर हमले का आरोप लगाते हए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यसमिति की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ 'संविधान बचाओ अभियान' को जन आंदोलन का रूप देने की रणनीति बनाई गई। इसके तहत पूरे



कई मुद्दों पर नेताओं ने किया मंथन

बैठक में अन्य मुद्दों जैसे– ओबीसी आरक्षण, सरना धर्म कोड, पेसा कानून, लैंड बैंक, नगर निकायों में आरक्षण और आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट की गई। इन मुद्दों को लेकर सरकार से संवाद स्थापित कर समाधान का प्रयास किया जाएँगा। इस अभियान का समन्वयक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचु को बनाया गया है, जबिक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का प्रभारी सूर्यकांत शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उनके साथ किशोर शाहदेव, एम तौसीफ, सुरेन राम, नरेंद्र लाल गोपी, सुंदरी तिर्की, अख्तर अली, जितेंद्र त्रिवेदी, प्रेमनाथ मुंडा और हिमांशु सदस्य के रूप में रहेंगे।

राज्य में 'संविधान बचाओ रैली' आयोजित की जाएगी। जिसमें जनभागीदारी को बढावा देने पर

भागीदार बनने जैसा होगा।

रांची नगर निगम की ओर से दुकानों के लिए मांगे गए हैं आवेदन

महिलाओं के लिए सम्मान के तौर

मोरहाबादी वेंडर मार्केट में दुकानदारों को दिया जाएगा चबूतरा

रांची नगर निगम मोरहाबादी स्थित बिजली ऑफिस के समीप वेंडर मार्केट जोन-2 में स्थानीय फुटपाथ विक्रेताओं के लिए नवनिर्मित बाजार स्थल (चब्रतरा) का आवंटन करेगा। यह मार्केट उन फुटपाथ विक्रेताओं को एक ही छत के नीचे व्यवसाय का अवसर देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो वर्षों से मोरहाबादी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार ऐसे फुटपाथ विक्रेता जिनका नाम वर्ष 2016 में किए गए सर्वेक्षण में शामिल है या जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर निगम कार्यालय आदेश संख्या-300/डे-एनयूएलएम दिनांक 05.03.2022

लॉटरी से किया जाएगा दुकानों का आवंटन

विक्रेताओं को एक ही छत के नीचे व्यवसाय का मिलेगा अवसर

जनके पास वेंडर आईडी कार्ड व सर्टिफिकेट, वे स्थल पाने के होंगे पात्र

23 से 29 अप्रैल के बीच निगम कार्यालय में जमा करना होगा

से पूर्व पंजीकृत थे, उन्हें दुकान

आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने का

मौका मिलेगा। वहीं जिनके पास

रांची नगर निगम द्वारा जारी वेंडर



आईडी कार्ड व सर्टिफिकेट है, वे

इस मार्केट में स्थल पाने के पात्र

होंगे। इसके अतिरिक्त वैसे विक्रेता

जिन्हें अस्थायी रूप से एमटीएस

जांच के बाद होगी लॉटरी आवेदन पत्रों की जांच के

बाद स्थल आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। आवंटित स्थल पर विक्रेताओं को सात दिनों के भीतर दकान स्थापित करनी होगी। साथ ही, विक्रेता स्थल का हस्तांतरण या किराये पर देना प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें निगम के निदेशीं का पालन करना होगा।

एवं रजिस्ट्री ऑफिस के पास पुनर्वासित किया गया था, वे भी इस योजना के अंतर्गत चब्रुतरा पाने के

एक हफ्ते में देना होगा आवेदन



इन सभी पात्र विक्रेताओं को 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच रांची नगर निगम कार्यालय के सतह तल स्थित डे एनयूएलएम शाखा के काउंटर पर अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ सर्वेक्षण पावती की प्रति, पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र), पासपोर्ट साइज फोटो आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निजी स्कुलों की मनमानी पर लगेगी लगाम : एसोसिएशन

RANCHI: झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने उपायुक्त रांची की ओर से निजी स्कूलों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है। इस बैठक में पीटीए (पैरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन) के गठन से लेकर बीपीएल कोटे की सीटों पर हो रही गड़बड़ियों पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में सामने आई अनियमितताओं ने यह साफ कर दिया कि कई निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उपायुक्त रांची की यह पहल लंबे समय से अभिभावकों की ओर से उठाई जा रही मांगों को गंभीरता से लेने का संकेत है।

झारखंड राज्य राब्ता हज कमेटी ने आजमीन-ए-हज को दिया प्रशिक्षण

मंगलवार को झारखंड राब्ता हज कमेटी ने हजयात्रा पर जाने वाले आजमी-ए-हज को हज से संबंधित जानकारी दी। राजधानी रांची के नाला रोड स्थित इमाम हाउस में हज तरिबयती कैंप का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता-सह-झारखंड राब्ता हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी हाजी मतलूब इमाम ने की और संचालन कमेटी के महासचिव हाजी मुख्तार ने किया। हजरत मौलाना ओबैदुल्लाह कासमी ने प्रशिक्षण दिया। मौलाना ने बताया कि हज का पहला दिन मक्का मुकर्रमा में एहराम बांधकर एहराम की हालत में मीना को रवानगी,दूसरा दिन फजर की नमाज मीना में अदा कर-के सूरज निकलने के बाद मीना से चलकर सूरज ढलने से पहले दुआ



पढ़ते हुए अराफात पहुंचना है। हज के तीसरे दिन मुज्दल्फा में फजर की नमाज के बाद कुछ देर ठहरना और सुरज निकलने से कुछ देर के पहले मीना रवाना हो जाना आदि है। इसके साथ हज से संबंधित बातें विस्तार से बताई गईं। आए हुए तमाम लोगों का स्वागत साफा, तस्बीह आदि देकर राब्ता कमेटी ने किया। मौके पर हाजी मतलूब इमाम, हाजी मुख्तार, मौलाना ओबैदुल्लाह कासमी, मो रुस्तम, कलीम खान, डॉक्टर आफताब अहमद, मो राशिद, शाहिद एहसान आदिल मौजूद थे।

समाचार सार

ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता 27 से CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में

उद्योगपित पदम कुमार जैन द्वारा प्रायोजित 14वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता रविवार

27 अप्रैल से शुरू होगी। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिला के मान्यताप्राप्त विद्यालय भाग

महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मान्यताप्राप्त विद्यालय के सिर्फ वही छात्र भाग ले सकते हैं, जिनकी जन्मतिथि 1 सितम्बर 2009 या उसके बाद की हो। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। 20-20 ओवर के मैच लीग कम नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल 18 मई को होगा।

शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने डॉ. दिलचंद राम



GHATSILA: घाटशिला कॉलेज शिक्षक संघ की बैठक मंगलवार को डॉ. पीके गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इस दौरान सर्वसम्मित से अध्यक्ष डॉ. दिलचंद राम, सचिव प्रो. राम विनय कुमार श्याम और कोषाध्यक्ष प्रो. महेश्वर प्रमाणिक को चना गया। विदित हो कि घाटशिला महाविद्यालय शिक्षक संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका था। यह भी निर्णय लिया गया कि संघ की बैठक प्रत्येक तीन महीने पर होगी। मार्च 2025 तक सभी शिक्षकों का अंशदान टाक कोष में जमा कर दिया जाएगा। बैठक में डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संदीप चंद्र, प्रो. इंदल पासवान, डॉ. कुमार विशाल, प्रो. मो. सज्जाद, डॉ. संजेश तिवारी, प्रो. विकास मुंडा

कर्मचारी महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष बने सुरेश राम



GHATSILA: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की घाटशिला प्रखंड स्तरीय बैठक मंगलवार को धरमबहाल पंचायत भवन में हुई। इसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। कमेटी में प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राम, कार्यकारी अध्यक्ष अमर पांडेय, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, जयंत कुमार भगत, शालिनी कुमारी, मंगल दुडू एवं वंदना सिंह, प्रखंड मंत्री धरम् उराव, उप प्रखंड मंत्री नहरु प्रसाद धारा, संयुक्त मंत्री लक्ष्मीकांत महतो, अंकिता कुमारी, प्रियंका कुमारी, सोमनाथ बोदरा एवं रायमनी सोरेन, कोषाध्यक्ष अविनाश कुमार मोहंती, सह कोषाध्यक्ष नेहा कुमारी, कार्यालय मंत्री मानस कुमार पाल, अंकेक्षक आशुतोष चौबे, संघर्ष मंत्री मानिक राम सोलंकी, उप संघर्ष मंत्री सोनाराम किस्कू आदि बनाया गया।

पाक कला प्रतियोगिता-सह-पोषण पखवाडा संपन्न

CHAIBASA: जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा जिलास्तरीय पाक



पखवाड़ा का समापन मंगलवार को हुआ। इसमें प्रथम लीलामुनी आंगनबाड़ी केंद्र फुलहातु-बी, प्रखंड सदर चाईबासा, द्वितीय जम्बुवती देवी,

2, प्रखंड- नोवामुंडी व तीसरे स्थान पर मीरा देवी आंगनबाड़ी केंद्र बड़ाजामदा-1, प्रखंड नोवामुंडी को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त कलदीप चौधरी ने कहा कि पाक कला प्रतियोगिता में सहायिकाओं द्वारा विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला की तरफ से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्वेता भारती ने कहा कि पोषण पखवाड़ा की शुरूआत 8 अप्रैल को हुई थी, जो मुख्यतः चार थीम पर आधारित थी। पहला जीवन के प्रथम 1000 दिन, दूसरा, लाभार्थी मॉड्यूल को बढ़ावा देना, तीसरा समुदाय स्तर पर अति गंभीर कुपोषित बच्चे का प्रबंधन एवं चौथा बच्चों में मोटापा कम करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना। पखवाडा के अंतर्गत पिछले 14 दिनों में 1 लाख से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन आंगनबाड़ी, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर किया गया। कार्यकम में लगभग 200 सेविका-सहायिका व महिला पर्यवेक्षिका भी उपस्थित थीं।

यूनियन उपचुनाव में 5 ने लिए नामांकन पत्र

JAMSHEDPUR : टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के फाउंड्री डिवीजन में रिक्त हुए कमेटी मेंबर के एक सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मंगलवार को 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया। दरअसल यनियन के अध्यक्ष गरमीत सिंह तोते के रिटायर होने के बाद यह सीट खाली हुई है। मंगलवार को टाटा मोटर्स के पुराने कैंटीन में चुनाव संचालन समिति की देखरेख में नामांकन पत्रों का वितरण किया गया। 24 अप्रैल को नामांकन पत्र जमा लिए जाएंगे।

युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर दो वर्ष से यौन शोषण करने का आरोप

युवती ने मझगांव थाने में दर्ज कराई शिकायत, कहा- शादी की बात पर मारपीट कर भगाया

पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव में एक युवक पर शादी का झांसा देकर युवती ने यौनशोषण का आरोप लगाया है। यवती के अनुसार, शादी की बात पर उसने मारपीट कर भगा दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद मझगांव थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए चाईबासा भेज दिया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ युवती ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की शिकायत 21 अप्रैल को दर्ज कराई थी।

जानकारी के अनसार, मंझारी प्रखंड की पीड़िता मंजू कुमारी (बदला हुआ नाम) ने शिकायत में दर्ज कराया है कि यवक 22-23 महीना पहले एक शादी समारोह में भाग लेने मझगांव गया

PHOTON NEWS JSR:

मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र में

खडिया बस्ती स्थित तिर्की गार्डेन

के पीछे क्रिकेट मैदान में 19

अप्रैल को हुई कारपेंटर ननकू

लाल की हत्या की घटना का

पुलिस ने खुलासा कर दिया है।

पुलिस ने इस मामले में खड़िया

बस्ती के ही रहने वाले कृष्ण

सिंह उर्फ लल्ला और उलीडीह

के ही डिमना रोड स्थित

स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट निवासी

जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया

पूछताछ में पता चला कि हत्या

की इस घटना में एक अन्य

यवक भी लिप्त है। पलिस इस



किसी और से शादी करने वाला था युवक

इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपी युवक किसी और से शादी करने वाला है, और रिपोर्ट करने पर पीड़िता को धमकी दे रहा था। ऐसे में पीड़िता ने अखिर 22 अप्रैल को थाना में शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद टीम गढित कर आरोपी की तलाश में रवाना किया, लेकिन तीनों घर से फरार हैं।

आलम से परिचय हुआ था। बाद में अपने प्यार के जाल में मुझे आरोपी ने शादी का झांसा देकर आ रहा था। जब मैंने शादी करने

उलीडीह के ननकू हत्याकांड का पुलिस ने

किया खुलासा, दो हत्यारोपियों को भेजा जेल

अरशद आलम, उसके पिता भगा दिया और खुद धमकी देने

मामला सामने आया है। आरोपी सीताराम गिलुवा (30) ने आम का लालच देकर बच्ची को झाड़ी में बुलाया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची चिल्लाई तो आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को

सिंहभम जिला के सोनवा में 8

साल की बच्ची से दुष्कर्म का

सोनुवा थाना अंतर्गत आमबगान में नाबालिग आम तोड़ने गई थी, लेकिन वह आम तोड नहीं पा रही थीं। इसी दौरान संरडियापोस गांव निवासी सीताराम गिलुवा बच्ची को अकेला देखकर उसे आम देने का लालच देकर झाड़ियों में ले



पुलिस गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी

सोनुवा में ८ साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। लेकिन, बच्ची ने अचानक चिल्ला दिया, जिसके बाद आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। तब तक आसपास में लोगों ने बच्ची की आवाज सुन ली थी। जब लोगों ने झाड़ी में जाकर देखा तो उसकी साथ युवक दुष्कर्म कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद मे

लोगों ने आरोपी को सोनुवा थाना की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने नाबालिंग के बयान पर आरोपी सीताराम गिलुवा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को

पशुपालन विभाग के कर्मियों का चार माह से वेतन लंबित

GHATSILA : पशुपालन विभाग अंतर्गत अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी घाटशिला का पद जनवरी से रिक्त है, जिसके कारण अनुमंडल के कर्मचारियों का वेतन 4 माह से लंबित है। इस संबंध में कार्यालय के कर्मियों ने बताया कि पूर्व के प्रभारी पदाधिकारी डॉ. स्रेंद्र कुमार की सेवानिवृति के उपरांत लगभग चार माह बाद भी किसी पदाधिकारी को प्रभार नहीं दिया गया है। इसके कारण चार माह से कर्मियों की वेतन निकासी नहीं हो रही है। कर्मियों के समक्ष भरण–पोषण से लेकर बच्चों की पढ़ाई एवं पारिवारिक सदस्यों की अनिवार्य चिकित्सा सेवा तक बाधित है। कर्मियों ने वरीय पदाधिकारियों से आग्रह कर समस्या का निराकरण करने की मांग की है, परंतु हर स्तर से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कर्मियों ने बताया कि दो-चार दिनों में अगर वेतन निकासी की व्यवस्था नहीं हुई, तो वे बाध्य होकर सामूहिक रूप से झारखंड उच्च न्यायलय

टाटा मोटर्स कर्मी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत

के बाईसिक्स (अस्थायी) कर्मी पी. मार्डी की कंपनी में तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे टेल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान उसने सोमवार की रात दम तोड़ दिया है। कर्मी के परिजनों ने 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग रखी है। उनकी मांग है कि इसके साथ ही एक आश्रित को नौकरी दी जाए। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने बताया कि परसुडीह के प्रधान टोला निवासी पी. मार्डी 19 अप्रैल को ड्यूटी पर गए थे। वहीं, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रबंधन ने उन्हें इलाज के लिए टेल्को अस्पताल में भर्ती कराया था। पी. मार्डी तीन भाइयों में मंझला था। वही घर में अकेला कमाने वाला था। 10 लोगों के पालन-पोषण का भार उस पर था।



मृतक की फाइल फोटो

इसलिए परिजन जोर दे रहे हैं कि एक आश्रित को नौकरी दी जाए और 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। परिजनों का कहना है कि प्रबंधन उनसे वार्ता कर रहा है। अगर प्रबंधन उनकी मांग नहीं मानता तो वह आंदोलन करेंगे। झामुमो नेता पलटन मुर्मू का कहना है कि मांग नहीं माने जाने पर टाटा मोटर्स का गेट जाम किया जाएगा। जब तक उन्हें मुआवजा और आश्रित को नौकरी का एलान नहीं किया जाता, तब तक पी. मार्डी का

है। इनके पास से पुलिस ने हत्या युवक की तलाश में छापामारी में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, दो कर रही है। बताया जा रहा है कि कारतूस, एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और मृतक का कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला से ननकृ रियलमी कंपनी का स्क्रीनटच लाल का विवाद चल रहा था। मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों के बीच कई बार मारपीट

हुई थी। लल्ला और जसबीर क्रिकेट मैदान में बैठ कर दारू पी रहे थे। तभी उन्हें ननकू लाल दिख गया। इन दोनों ने ननकू लाल को दबोच लिया और गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। बताते हैं कि कृष्णा सिंह और जसबीर सिंह दोनों क्रिकेट मैदान में अक्सर अड्डेबाजी करते थे। घटना 19 अप्रैल की रात को ही अंजाम दे दी गई थी।

मंत्री के खिलाफ भाजपा ने निकाली आक्रोश रैली



घाटशिला में बाइक रैली निकालते कार्यकर्ता

GHATSILA: राज्य सरकार के मंत्री हफीजल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा जिला कमेटी द्वारा मंगलवार को आक्रोश रैली निकाली गई। रैली मऊभंडार के अंबेडकर चौक से मुख्य पथ होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची। जिला अध्यक्ष चंडीचरण साह के नेतृत्व में अनमंडल पदाधिकारी पदाधिकारी सनील चंद्र को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चंडीचरण साह ने बताया कि राज्यपाल से मांग की गई है कि राज्य सरकार संपोषित संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रही है। संविधान की शपथ लेकर पद पर आसीन होने वाले मंत्री संवैधानिक मयार्दाओं को तार-तार कर रहे हैं। बिगत दिनों हफीजुल हसन ने बयान दिया था कि हम कुरान को दिल और संविधान को हाथ में रखते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि 'मेरे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में। दोनों बयान संविधान की मयार्दाओं का उल्लंघन है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

डीबीएमएस की पूर्व प्रिंसिपल मीना बगली का निधन

JAMSHEDPUR : डीबीएमएस कदमा की पर्व प्रिंसिपल मीना

सोमवार को निधन गया । 64 वर्षीय मीना ब्रेस्ट बगली और

कैंसर बोनमैरो की बीमारी से ग्रसित थीं। वह टीएमएच में इलाजरत मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पर किया गया। सर्किट हाउस निवासी उनके फ्रमरोज बगली ने बताया कि घर में पारसी रीतिरिवाज के अनुसार क्रियाकर्म किया जा रहा है। पत्नी के रिश्तेदार मुंबई एवं अन्य इलाकों से पहुंच रहे हैं। उठाला व प्रार्थना सभा पंजाबी आर्य

समाज रीतिरिवाज से होगी।

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, पुलिस को मिले टोस सुराग

सिंह की हत्या के तीन दिन बाद मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा मानगो स्थित आस्था स्पेस टाउन से निकली, जिसमें समाज के तमाम वर्गों से लोग शामिल हुए। शव यात्रा सीतारामडेरा, भुइयांडीह होते हुए सुवर्णरेखा बर्निंग घाट पहुंची, जहां अंतिम संस्कार किया गया। इसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भी शामिल हुए। दुसरी तरफ, पुलिस को कुछ ठोस सुराग हाथ लगे हैं। इसके जरिए पलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। वहीं पलिस कई एंगल पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही घटना का खलासा करेगी। करणी सेना की तरफ से भी पुलिस पर काफी दबाव है। विनय सिंह के शव के पास एक देसी पिस्टल मिला था।



विनय सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल लोग

अर्जुन मुंडा व रघुवर दास ने सरकार को घेरा वेनय सिंह की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। राज्य के पूर्व मख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढाढस बंधाया और कहा कि यह हत्या राज्य की कानून—व्यवस्था की नाकामी को दशार्ती है। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि विनय सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इस तरह से उनकी हत्या से आम लोगों के मन में भय का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और राज्य में कानून का कोई खौफ

उन्होंने कहा कि राज्य में क्राइम का ग्राफ दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते, जमशेदपुर में रहूंगा

नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दासँ ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर पत्रकारों से कहा कि अभी तक पुलिस ने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती, मैं जमशेदपुर में ही रहूंगा। यहीं नहीं, उन्होंने कहा कि रोज एसपी ऑफिस में बैटूंगा।

मिटाई कारीगर की मौत मामले

ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए घर में जैव कीटनाशक निर्माण पर हुई कार्यशाला

टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में मिट्टी संरक्षण के सिखाए गए गुर

PHOTON NEWS JSR:

टाटा स्टील जुलॉजिकल पार्क ने मंगलवार को अर्थ डे मनाया। इस अवसर पर पटमदा प्रखंड के ग्रामीण युवाओं के लिए घर पर जैव-कीटनाशक बनाना विषय पर कार्यशाला हुई। यह कार्यशाला बिदु चंदन ट्रस्ट फॉर ट्राइबल सेल्फ-एम्पावरमेंट से जुड़े पलाशबनी गांव (जो लौहनगरी की सीमा पर राष्ट्रीय उच्चपथ-33 के किनारे स्थित है) के उत्साही प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम था झ आवर पावर, हमारा प्लानेट। मिट्टी की उर्वरता और उसकी जैव विविधता को बनाए रखना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो ना ही हमारे लिए जरूरी पौधे पनप पाएंगे और ना ही पशु-पक्षियों का



टाटा जू में जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण लेतीं महिलाएं व छात्राएं

जीवन सुरक्षित रहेगा। दुर्भाग्यवश, असंतुलित कृषि पद्धतियों के कारण उपजाऊ मिट्टी तेजी से नष्ट हो रही है। ऐसे में आज के युवाओं को पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह संसाधन सुरक्षित रह सकें। इस अवसर पर जैविक और

पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक बनाने की कार्यशाला का संचालन डॉ. सीमा रानी (जीवविज्ञानी एवं शिक्षा अधिकारी, टाटा जू) ने किया। उन्होंने किचन गार्डन या घर के पिछवाड़े में उपलब्ध सामान्य सामग्रियों से जैव-कीटनाशक बनाने की सरल प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित किया।

सुदूर गांवों की बच्चियों ने सीखा किशोरावस्था व पीरियड का विज्ञान

JAMSHEDPUR : विश्व पृथ्वी दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड गुड़ाबांधा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय से कोल्हान स्तरीय मेंस्टुअल सॉलिडरिटी इनिशिएटिव की शुरूआत की गई। सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन, प्रोजेक्ट बाला व क्युआरजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मेंस्ट्रुअल सॉलिडरिटी इनिशिएटिव के माध्यम से किशोरियों व महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रियूजेबल पैड के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि सामान्य सैनिटरी पैड का निस्तारण अब इंसानों के लिए बड़ी समस्या बन कर उभर रहा है, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नैपकिन के नष्ट होने में सैंकड़ों सालों तक का समय लगता है।

विद्यार्थियों ने लिया धरती की रक्षा का संकल्प

CHAKRADHARPUR : राजा नरपत सिंह बालिका उच्च विद्यालय व रानी रसाल मंजरी स्कूल ने मंगलवार को विश्व पथ्वी दिवस व जल संरक्षण पखवाडा के उँपलक्ष्य में कार्यक्रम किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने धरती के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम किए। कार्यक्रम की

शुरूआत सामूहिक प्रार्थना से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद छात्र–छात्राओं ने पृथ्वी संरक्षण पर भाषण, कविता पाठ तथा लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिससे सभी को धरती के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध हुआ विद्यालय की प्राचार्य सविता महतो ने बच्चों से कहा कि हमारी धरती मां संकट में है और उसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक बच्चा अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाए और उसका पालन-पोषण करे, तो यह धरती पुनः हरी-भरी हो सकती है। सभा के उपरांत विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विद्यालय एक जागरूक रैली निकाल कर लोगों को पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ ... जल ही जीवन है ... जल है तो कल हैआदि स्लोगन से जागरूक किया गया। इससे पहले विद्यालय परिसर

में पौधारोपण किया गया। विद्यालय में धरती बचाओ विषय पर चित्रकला एवं निबंध

प्रतियोगिता भी हुई। कार्यक्रम में नीतू साहू, पदमाशीनी, तनु सिंह, श्रवण महतो, अभिनव कुमार, यशोदा महतो, हारा प्रधान, शिल्पी आनंद आदि सक्रिय रहे।



स्थित मिठाई दुकान रतन स्वीट्स में कार्यरत कारीगर की 17 अप्रैल को मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मृतक के भाई जितेंद्र चौधरी एवं परिवार के अन्य लोगों ने मंगलवार को एसएसपी से मिले। जितेंद्र चौधरी ने एसएसपी से आग्रह किया है कि मेरा छोटे भाई छोटू चौधरी की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी। घटना को लेकर मैनेजर

संदेह है। वहां मौजूद रहने बाले मैनेजर रामू भुई, टास्क नायक, उज्जवल प्रमाणिक, उमेश प्रातर, कृष्ण गोराई, जितेन महतो, कमलेश दास, परिमल दास, सैमसंग हांसदा, दुकान के मालिक किशोर कुमार सेन, उनका बेटा

अभिजित कुमार सेन ने मिलकर



एसएसपी ऑफिस पहुंचे लोग

इस घटना को अंजाम दिया है। मेरा भाई ही मेरी मां, पिता और कुंवारी छोटी बहत का पालन-पोषण व देखभाल करता था। एसएसपी से आग्रह किया कि उचित जांच कर सभी दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मेरे परिवार को न्याय मिल सके।

O BRIEF NEWS रोहतास में बाइक व स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन की मौत

DEHRI-ON-SONE : बिहार में रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर सोमवार की देर रात एक स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पुलिस के अनसार मतकों की पहचान नोखा थाना क्षेत्र के मजन गांव निवासी मंतोष कुमार 20 वर्ष, भअर कमार 18 वर्ष व सजन कुमार 22 वर्ष के रूप में की गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो पर बीईओ दावथ का बोर्ड लगा है। बाइक सवार तीनो युवक अपने गांव से रामनगर शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे तभी स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी।

अस्पताल में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि की हुई मौत लापरवाही का आरोप

EAST CHAMPARAN: जिला के सुगौली नगर पंचायत के वार्ड पार्षद पति सह सुगौली नगर के राजद अध्यक्ष मुस्ताक आलम (45) की मौत हो गई। बताया गया कि वे पथरी के ऑपरेशन के मोतिहारी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती हुए थे। जहां उनका दो दिन पर्व ऑपरेशन हुआ था। सोमवार देर रात करीब डेढ़ बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी जिसके बाद उनके परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर को खोजा। लेकिन अस्पताल में कोई मौजूद नही था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। मंगलवार अहले सुबह इलाज के अभाव में उन्होने दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जिसके बाद अस्पताल के सभी कर्मी मौके से फरार हो गये। परिजनों का आरोप है कि इतने बड़े अस्पताल में रात में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसलिए समय पर इलाज नहीं मिल सका।

विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन

BHAGALPUR: जिले के सन्हौला प्रखंड में विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकताओं ने इरशाद आलम के अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। जिसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, अपहरण पर रोक लगाने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस लेने, प्रधानमंत्री आवास सर्वे सूची में सभी गरीबों का नाम बिना भेदभाव शामिल करने. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 4 लाख करने, स्मार्ट मीटर खत्म करने और गलत बिजली बिल में सुधार के लिए शिविर लगाने, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने सहित कई अन्य मांगे शामिल हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सन्हौला थाना एवं आमडंडा थाना अध्यक्ष का गठजोड़ शराब माफिया और दलालों से हो गया है।

'शहर आपकी बात' के तहत शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी विकास योजना का लिया जायजा

नीतीश कमार ने आज, मंगलवार को अण्णे मार्ग स्थित 'संकल्प' में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 'आपका शहर आपकी बात' बिहार में शहरीकरण के बढते कदम कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम से विवरणिका अवलोकन किया और मोबाइल एप से सूचना संग्रहण की जानकारी ली। समीक्षा के पश्चात मुख्यमंत्री ने 'आपका शहर-आपकी बात' जागरूकता रथ का निरीक्षण भी किया। तय हुआ कि अभियान का शुभारंभ 25 अप्रैल को किया जायेगा।

समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि ईसाई धर्मगुरू पोप फ्रांसिस के निधन के कारण देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है, इसके चलते 'आपका शहर आपकी बात' कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ 25 अप्रैल को किया जायेगा। सबसे महत्वपर्ण विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों की सिक्रय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल से न केवल नगरों की भौतिक स्थिति में



शासन में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री के इस दुरदर्शी विचार के अनरूप यह अभियान शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा सशक्त और समावेशी शहरी बिहार के निर्माण की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2006 में 123 नगर निकाय थे जो वर्ष 2025 में बढ़कर 261 हो गये हैं। सभी बेहतर ढंग से फंक्शनल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के

अनसार राज्य की शहरी जनसंख्या 1.57 करोड़ है जो कि राज्य की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, जलापूर्ति, उपलब्धता एवं उन्नयन अत्यंत स्पष्ट है कि शहरीकरण तेजी से आवश्यक है ताकि शहरी जीवन बढ़ रहा है और इसके साथ ही को सुगम और व्यवस्थित बनाया जा सके। नगर विकास सचिव ने नागरिक सुविधाओं की माँग भी बढ़ी है। शहरीकरण के तेजी से बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा शहरी आधारभत बढ़ते क्रम में कई ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां नागरिकों को संरचना की मजबूत करने की सुविधाओं दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में प्रगति आवास, सड़क, नाला,

कुल 1,696.17 करोड़ की लागत से 25 विभिन्न नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। नगर निगमों और नगर परिषदों के क्षेत्र विस्तार के बाद ऐसे वार्ड जहां नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता करायी जानी है, वहां 'आपका शहर-आपकी बात' कार्यक्रम के अंतर्गत 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में कुल 2491 कार्यक्रम का आयोजन

समाज से कुपोषण के खात्मे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन



AGENCY NAVADA : समाज से कुपोषण रूपी कोढ़ के खात्मे के लिए मंगलवार को नवादा जिले के सभी बाल विकास परियोजना आयोजन कर शपथ ग्रहण कराया गया। कौवाकोल बाल विकास परियोजना में में पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पर्यवेक्षिकाओं ने सेविकाओं को कपोषण मिटाने के मामले में सजगता से काम करने की बात कही ।पोषण पखवाड़े के अभियान चलाया जा रहा है । इस अभियान के तहत कौवाकोल प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी कुपोषण के खात्मे का अभियान चलाया जा रहा है।

कुमारी, कुमारी,प्रधान सहायक विपिन कुमार के साथ ही उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं ने भी कुपोषण की खात्मे का शपथ ग्रहण के साथ संकल्प लिया। सेवकाओं को बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले तथा गरीब तबके के लोगों के घरों में जाकर कुपोषित बच्चों तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान देना है तथा उसके निवारण के उपाय भी

अति कपोषित बच्चों की सची कार्यालय को भेजना है। ताकि सरकार द्वारा प्रदत सुविधाओं के अनुसार उसका बेहतर इलाज कराया जा सके। 8 अप्रैल से चलने वाले पोषण पखवाड़े का आज मंगलवार को समापन किया गया इस बीच सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण की खात्मे के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए।

शौर्य दिवस के रूप में कुंवर सिंह की जयती मनाएगी साइबर ढगी मामले में 5 गिरफ्तार सरकार, वायुसेना के विमान देंगे सलामी : सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा

कि 1857 के महान स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती को सरकार शौर्य दिवस के रूप में मनायेगी। इस अवसर पर पटना में दो दिन के एयर शो का शुभारम्भ आज वायुसेना के विमानों ने किया। कल (23 अप्रैल) का मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से पटना में लडाकु विमानों का रंगारंग एयर शो पहली बार हो रहा है और इसके साथ ही पहली बार कुंवर सिंह जयंती समारोह की भव्यता को



आसमान पर पहुंचाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि एयर शो के पहले दिन आज मंगलवार को वायुसेना के बिहटा एयर बेस से उड़ान भरने वाले नौ सूर्य किरण विमानों का हैरत अंगेज

करतब 40 से अधिक स्कूलों के सैंकड़ों बच्चों ने देखा, जिससे उनमें देशभक्ति और वीरता की भावना का संचार हुआ। उन्होंने कहा कि एयर शो के 23 अप्रैल

नीतीश कुमार शामिल होंगे। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि कल के एयर शो में आकाशगंगा की टीम तिरंगे के साथ कुंवर सिंह की तस्वीर लेकर आकाश में सलामी देगी। यह पहला मौका है। जब बिहार की धरती पर वायुसेना के माध्यम से वीर कुंवर सिंह को हवाई सलामी दी जाएगी। ईसाई धर्म गुरु पोप के निधन पर राष्ट्रीय शोक होने के कारण किसी तरह का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होगा. लेकिन भारतीय वायुसेवा की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा 9 हॉक 132 जेट विमानों के साथ

06 घंटे के अंदर ऑनलाईन लोन

पोषण सप्ताह के अवसर पर बाल

विकास परियोजना कार्यालय में

आयोजित पोषण कार्यक्रम में

महिला पर्यवेक्षिका माधवी कुमारी,

AGENCY BHAGALPUR जिले के साइबर थाना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सभी आरोपित को 06 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। उक्त आशय की जानकारी मंगलवार को साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने आज दी। डीएसपी ने बताया कि भागलपुर साइबर थाना के द्वारा साइबर फ्रॉड से संबंधित प्राप्त आवेदन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बीते 21 अप्रैल को झांसा देकर ऑनलाईन लोन देने के नाम पर ठगी करने एवं पैसे मांगने गये लोगों को बंधक बनाने की सूचना भागलपुर साइबर थाना

को प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन



एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर निगरानी एवं उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष, भागलपुर साइबर थाना के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। उक्त गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र देने के नाम पर ठगी करने वाले कुल 05 व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं बंधक बनाए गये लोगों को मुक्त कराया गया। अनुसंधान जारी है। उल्लेखनीय है कि माला देवी से 08 लाख रुपया, पार्वती देवी से 04 लाख, पूनम देवी से 1.5 लाख, गुड़िया देवी से 01 लाख, अजमेरी खातुन से 50,000 हजार, नविशा खातुन से 35 हजार, सरिता देवी से 20 हजार एवं कनीजिया खातन से 10 हजार की ठगी कर ली गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में रवि शेखर उर्फ मनोज साह, सुलेखा देवी, गडिया देवी, बेबी देवी और

पति की मौत, बाल-बाल बचीं पत्नी व बच्ची

सगौली-रक्सौल रेल मार्ग में शीतलपुर रेलवे ढाला के समीप में रेल लाइन पार कर रहे टैक्टर के ट्रेलर से दब जाने से बाइक सवार एक की मौके पर हीं मौत हो गई। वहीं साथ में बाइक पर सवार पत्नी और बेटी बाल-बाल बच गई। मृतक पलनवा थाना क्षेत्र के बस्टी निवासी जोखू खान का पुत्र फैयाज खान(30) बताया गया है।

परिजन के अनुसार मृतक अपने ससुराल जगदीशपुर से अपनी पत्नी शबनम खातून और पुत्री अलिफा के साथ बाइक से सुगौली थाना क्षेत्र के नकरदेई में ब्याही अपनी छोटी साली के ससुराल जा रहा था। जब वह शीतलपुर रेल ढाला के नजदीक पहुंचा तभी उसके चल रहे गिट्टी लदी ट्रैक्टर जो रेल लाइन पार कर रहा था लेकिन ट्रेक्टर पर अधिक



गिट्टी लदी होने के कारण वह चढ़ सका और पीछे की तरफ लुढक गया,जिसके पीछे चल रहे बाइक सवार टेक्टर की टाली से दब कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आसपास के लोगो की भारी भीड उमड़ पड़ी। लोगो ने ट्रेक्टर चालक को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी।सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगो की पिटाई से घायल चालक को अभिरक्षा में लिया। जबकि शव पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज रही है। परिजनो ने बताया कि मृतक अपने माता-पिता का एकलौता पुत्र था और उसके तीन बच्चे हैं।

ट्रैक्टर की ट्रॉली से दबकर बाइक सवार कलाम हत्याकांड : मर्डर में प्रयुक्त चाकू के साथ पुलिस ने सफीक को किया गिरफ्तार

नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीर बस्ती वार्ड नं-18 के पास गैयारी नहर रोड के किनारे चाय दुकानदार 40 वर्षीय कलाम का शव गला रेता मिला था। मामले में पुलिस ने सफीक नामक आरोपी की गिरफ्तार किया है। जानकारी एसपी अंजनी कमार ने आज दी। चाय दुकानदार एवं पार्ट टाइम में ई रिक्शा चलाने वाले कलाम की हत्या धारदार हथियार से किया गया था। सूचना पर तत्काल नगर थाना द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर एफसीएल टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन कराया गया। घटना के संबंध में अररिया थाना में मामला दर्ज किया गया था।

कांड के त्वरित उद्भेदन एवं



अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामपुकार सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष, अरिया एवं डीआईयू की विशेष टीम गठित कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी। टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान, आसूचना संकलन एवं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के आधार पर घटना के संदर्भ में एक प्लैटिना मोटर साइकिल पर

मृतक कलाम के साथ सवार दो अन्य व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था जिनके द्वारा मृतक को घटना स्थल पर साथ लाया गया था। तत्पश्चात टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामनगर वार्ड संख्या 27 के 30 वर्षीय सफीक पिता स्व. नूर मोहम्मद को हिरासत में लेकर पूछताछ में सफीक द्वारा आपसी विवाद को लेकर अपने सहयोगी के साथ कलाम की चाकू से गला रेतकर हत्या किया गया। अभियुक्त सफीक को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।

खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, महिला समेत चार झुलसे

AGENCY NAVADA: नवादा जिले के रजौली में मंगलवार को नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में एनएच 20 के किनारे महावीर पंडित के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण उसमें आग लग गई। आग जलते देख घर में अफरा-तफरी मच गई। घर में रहे पुरुष आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई।

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती। उससे पहले घर वाले आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, जिसमें नरेश पंडित,कौशल्या देवी, महावीर पंडित और नीतीश कुमार बुरी तरह से झुलस गए।जिसे आनन-फानन में आसपास के लोगों के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल



रजौली में भर्ती कराया। जहां ड्यूटी में तैनात चिकित्सक डॉ नवनीत नंदिनी ने प्राथमिक उपचार किया और सभी को खतरे से बाहर बताया है।फायर ब्रिगेड के अधिकारी राम अवध सिंह ने बताया कि सचना मिलने के बाद तुरंत हमलोग पहुंचे और आग पर काबू पाया है।उससे पहले ही घर के लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे।जिसमें चार लोग झुलस गए हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर इलाज के लिए बाहर

सुरक्षा, सेवा और सजगता का संदेश के साथ अग्निशमन सेवा सप्ताह संपन्न

आग से बचाव को लेकर रहें सतर्क : संदीप नायक

AGENCY BHAGALPUR जिले के एनटीपीसी कहलगांव द्वारा आयोजित फायर सर्विस सप्ताह मंगलवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर समारोह आयोजित किया गया। इसमें एनटीपीसी कहलगांव के कार्यकारी निदेशक संदीप नायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शरुआत सहायक कमांडेंट (अग्नि) मनीष कुमार द्वारा 'फायर सर्विस सप्ताह' के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए की गई। उन्होंने सप्ताह भर आयोजित मॉक ड्रिल्स, जनजागरूकता अभियानों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी साझा की तथा

वार्षिक अग्नि सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत



नायक कार्यकारी निदेशक ने अग्नि सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए सीआईएसएफ द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने फायर सर्विस सप्ताह के

दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कमांडेंट भारती नंदन ने उपस्थित जनसमूह को अग्नि सुरक्षा के प्रति सजग रहने का

सप्ताह भर संयंत्र के कर्मचारियों, श्रमिकों, सीआईएसएफ बल के सदस्यों तथा टाउनशिप स्थित विद्यालयों के बच्चों को अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव एवं सतर्कता

के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा द्वारा निरीक्षक काली चरण के नेतृत्व में एक उत्कृष्ट अग्नि प्रदर्शन किया गया। जिसकी मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा भूरि-भूरि सराहना की गई।

उल्लेखनीय है कि अग्निशमन सेवा सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति सजग करना तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों के प्रति शिक्षित करना है। यह सप्ताह सीआईएसएफ इकाई द्वारा पूरी गंभीरता एवं समर्पण के

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में डिजिटल ह्यूमैनिटीज पर हुआ सेमिनार का आयोजन

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा डिजिटल ह्युमैनिटीज विषयक एक सेमिनार का आयोजन किया गया।सत्र का नेतृत्व इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रख्यात विद्वान डॉ जय सिंह ने किया। डॉ जय सिंह ने डिजिटल ह्युमैनिटीज के उभरते हुए क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवीय अध्ययन में तकनीक की प्रासंगिकता और प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की, और यह दशार्या कि इसका ऐतिहासिक क्रम औद्योगिक क्रांति से लेकर आज के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अक) के युग तक कैसे फैला है। उन्होंने मार्शल मैक्लुहान जैसे विचारकों का हवाला देते हुए कहा कि



मशीनों के युग में मानव मन में गहरा परिवर्तन आया है। डॉ. सिंह ने मानव मस्तिष्क की तुलना हार्डवेयर से और मानव मन की तुलना सॉफ्टवेयर से की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को अक और तकनीकी विकास के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, अन्यथा अक मानव मन को नियंत्रित कर सकता है और पोस्ट-

ह्युमन युग में जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपकरण ग्रंथों के प्रचार-प्रसार और संरक्षण में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हमें मानविकी की मौलिक आत्मा को नहीं खोना चाहिए। डॉ. सिंह ने अकका मानव मनोविज्ञान पर प्रभाव समझाने के लिए प्लेसबो इफेक्ट की अवधारणा का उपयोग किया।

ल्ली विश्वविद्यालय में

छात्रों द्वारा क्लासरूम

सोशल मीडिया इंसाफ का नहीं रिश्तों की मौत का है नया मंच

सोशल मीडिया का बढता प्रभाव निजी जिंदगी में दखल के साथ ही अब रिश्तों के खात्मे की भी वजह बनता जा रहा है। आजकल लोग निजी झगड़ों और रिश्तों की परेशानियों को सोशल मीडिया पर लाइव आकर सार्वजनिक करने लगे हैं, जहां आधी-अधूरी सच्चाई दिखाकर सहानुभूति बटोरी जाती है। सुट्टा आली और मुक्का वाली जैसे मामलों में देखा गया कि जब दूसरा पक्ष सामने आया तो पहले समर्थन करने वाले लोग उलझन में पड़ गए। सोशल मीडिया अब इंसाफ का मंच नहीं, तमाशा बनता जा रहा है. जहां रिश्ते कंटेंट बनकर बर्बाद हो रहे हैं। इस डिजिटल दिखावे से बाहर निकलने का रास्ता संवाद, संयम और सच्चाई पर आधारित समझदारी है। रिश्तों को बचाने के लिए पहले उन्हें सार्वजनिक न करें, बल्कि निजी स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें। आधी सच्चाई दिखाकर न्याय मांगना रिश्तों की मौत का कारण बन सकता है। घर के अंदर की बातें अब घर की नहीं रहीं। एक वक्त था, जब दीवारों के भीतर जो होता था, वही दीवारों में दफन होता था, पर अब दीवारें भी वाई-फाई से जुड़ चुकी हैं और रिश्ते डाटा पैक पर टिके हैं। बात-बात पर फेसबुक लाइव, इंस्टा स्टोरी और यूट्यूब व्लॉग। यही अब नए जमाने का रिश्ता-निपटान मंच बन गए हैं। कोई थोड़ा-बहुत झगड़ा हुआ नहीं कि लोग कैमरा ऑन करके ऑडियंस के सामने आंसू बहाने लगते हैं। उस रोते चेहरे के पीछे कितनी सच्चाई है, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता, क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू अक्सर बेमौसम आता है या कभी आता ही नहीं। आजकल रिश्तों में सहनशीलता नहीं, स्क्रिप्टिंग आई है। जैसे ही किसी झगड़े या मनमुटाव की चिंगारी उठती है, लोग अपने कैमरे चालू कर लेते हैं और लाइव आकर खद को पीडित घोषित कर देते हैं। आवाज में कंपकंपी, आंखों में आंसू और शब्दों में दर्द, सब कुछ इतना रियल होता है कि देखने वाला पल भर में इमोशनल इन्वेस्ट कर बैठता है। अब सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया कोई अदालत है, जहां एकतरफा सबूत पेश करके दूसरे पक्ष को बिना सने सजा सनाई जा सकती है। क्या हम सब यजर्स अब जज बन चुके हैं और अगर हां तो हमारी अदालत में अपील की व्यवस्था कहां है। दिक्कत ये है कि आजकल लोग जज नहीं, जजमेंटल बन चके हैं। किसी भी मद्दे को बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांचे, बस वायरल होने की स्पीड से नापते हैं। कौन सही है से ज्यादा अहम हो गया है कौन पहले लाइव आया। दरअसल जब एक रिश्ते की दरार को सार्वजनिक किया जाता है तो उसका असर केवल उस रिश्ते पर नहीं, समाज पर भी पडता है। यह एक विकृति बनती जा रही है, जहां निजी दर्द सार्वजनिक मनोरंजन बन रहा है। इसे प्रोत्साहन मिलता है व्यूज, लाइक्स और फॉलोवर्स की भुख से। एक जमाना था, जब लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते थे, जबकि आज लोग लाइक और शेयर के लिए अपने रिश्ते खुद बर्बाद कर देते हैं। मीडिया से ज्यादा, मिडियाई मानसिकता दोषी है। यह केवल मीडिया ट्रायल' का मुद्दा नहीं है। असली समस्या उस मानसिकता की है, जो कैमरा ऑन होते ही खुद को पीड़ित घोषित कर देती है और दर्शकों को जूरी बना देती है। यह हाफ ट्रथ पॉलिटिक्स अब राजनीति तक सीमित नहीं रही । यह अब हमारे घरों में घुस चुकी है। लोग अपने ग़ुस्से और दुख को शब्दों में नहीं, स्क्रिप्टेड कंटेंट में ढाल रहे हैं। दर्शक भी असल में मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहते हैं, स्क्रीन के उस पार तालियां बजाते हुए। इस डिजिटल युग में रिश्ते अब संवाद से नहीं, कंटेंट से चलने लगे हैं। पार्टनर से बात करने की जगह, लोग सोशल मीडिया पर इन्डायरेक्ट पोस्ट करते हैं। लड़ाई होती है तो स्टोरी लगती है - सब कुछ सहने की भी एक हद होती है। फिर लाइक, कमेंट और शेयर की बाढ़ आती है, जो उस रिश्ते के फटे कपड़े में और कील ठोक देती है। आज जब हर व्यक्ति अपने हाथ में मीडिया लेकर घूम रहा है, तब सबसे बड़ा जिम्मेदार भी वही है। कैमरा ऑन करना आसान है, पर सच्चाई को ईमानदारी से दिखाना मुश्किल। रिश्ते भरोसे से बनते हैं और भरोसे की बुनियाद संवाद से मजबूत होती है, तमाशे से नहीं। हर बार लाइव आकर रोना-धोना करने से सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं बचते। जब दसरा पक्ष सामने आता है तो फिर न सिर्फ रिश्ता, बल्कि भरोसा भी मरता है, उस इंसान का भी और उस समाज का भी, जो बस लाइव देखकर न्याय करने को तैयार बैठा था। सवाल है कि क्या कोई रास्ता है इस डिजिटल डामा से बाहर निकलने का। बिल्कुल है। इसलिए अगली बार जब कोई रोता हुआ वीडियो सामने आए तो जरा रुकिए। सवाल पूछिए, दोनों पक्षों को सुनिए, क्योंकि असल इंसाफ वही है, जो तटस्थ हो और इंसाफ के बिना कोई भी तमाशा बस एक और रिश्ते की मौत होती है। उधर उन लोगों को भी सोशल मीडिया के बजाय झगड़े के समाधान के दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। जरूरी है कि किसी भी झगडे या विवाद को सार्वजनिक करने से पहले अपने सबसे करीबी से निजी तौर पर बात करें। संवाद हर समस्या का पहला समाधान है। अगर मामला गंभीर है, तो परिवार, मित्र या थेरेपिस्ट की मदद लें। जब समस्या होती है तो समाधान भी साथ ही होता है। हर कहानी के दो पहल होते हैं और कभी-कभी सच्चाई दोनों के बीच कहीं होती है। हर रिश्ता अपने आप में एक दुनिया होता

गोबर, गुस्सा और विश्वविद्यालय की गिरती गरिमा

ANALYSIS



विश्वविद्यालय अब संवाद के नहीं, सत्ता के मंच बनते जा रहे हैं, जहां छात्रों की असहमति को दबाया जाता है। इस असामान्य विरोध ने न केवल व्यवस्था की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी बताया कि प्रतीकों के जरिए भी तीखा प्रतिरोध संभव है। जब गुस्सा प्रतीकों के जरिए बोलता है, कभी-कभी गोबर से भी। दिल्ली विश्वविद्यालय जिसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है, हाल ही में एक अजीबोगरीब और प्रतीकात्मक विरोध का केंद्र बना कुछ छात्रों ने क्लास रूम की दीवारों पर गोबर लीप दिया और पिंसिपल के घर के बाहर भी गोबर फेंक दिया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, न ही कोई ग्रामीण उत्सव। यह था एक गुस्से से भरा राजनीतिक वक्तव्य। यह घटना न केवल ध्यान खींचती है, बल्कि कई गहरे और असहज सवाल भी खड़े करती है। क्या विश्वविद्यालय अब सिर्फ सत्ता का विस्तार बन चुके हैं। क्या छात्र आंदोलन केवल विचारों से नहीं, अब गंध से भी संवाद करने लगे हैं। यह विरोध दिल्ली यूनिवर्सिटी के हुआ. जहां छात्रों ने गोबर लिपकर क्लासरूम को पवित्र करने की कोशिश की। दरअसल, यह पवित्रता का तंज था, एक ऐसे सिस्टम पर, जिसे छात्र अपवित्र मानते हैं। कहा गया कि यह विरोध जातिगत भेदभाव, एक दलित प्रोफेसर के साथ अन्याय और प्रशासन की असंवेदनशीलता के खिलाफ था।

और प्रिंसिपल के घर पर गोबर लीपने की घटना केवल अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि एक गहरे असंतोष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। इस विरोध ने सत्ता और शिक्षा व्यवस्था के पाखंड को उजागर किया। जहां एक ओर गोबर को सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, वहीं जब छात्र उसी प्रतीक का इस्तेमाल विरोध में करते हैं. तो उसे असभ्य करार दिया जाता है। विश्वविद्यालय अब संवाद के नहीं, सत्ता के मंच बनते जा रहे हैं, जहां छात्रों की असहमति को दबाया जाता है। इस असामान्य विरोध ने न केवल व्यवस्था की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी बताया कि प्रतीकों के जरिए भी तीखा प्रतिरोध संभव है। जब असहमति की जगह छिन जाती है, तो गुस्सा प्रतीकों के जरिए बोलता है, कभी-कभी गोबर से भी। दिल्ली विश्वविद्यालय जिसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है, हाल ही में एक अजीबोगरीब और प्रतीकात्मक विरोध का केंद्र बना। कुछ छात्रों ने क्लास रूम की दीवारों पर गोबर लीप दिया और प्रिंसिपल के घर के बाहर भी गोबर फेंक दिया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, न ही कोई ग्रामीण उत्सव। यह था एक गुस्से से भरा राजनीतिक वक्तव्य। यह घटना न केवल ध्यान खींचती है, बल्कि कई गहरे और असहज सवाल भी खड़े करती है। क्या विश्वविद्यालय अब सिर्फ सत्ता का विस्तार बन चुके हैं। क्या छात्र आंदोलन केवल विचारों से नहीं, अब गंध से भी संवाद करने लगे हैं। यह विरोध दिल्ली यूनिवर्सिटी के

क्लासरूम को पवित्र करने की कोशिश की। दरअसल, पवित्रता का तंज था, एक ऐसे सिस्टम पर, जिसे छात्र अपवित्र मानते हैं। कहा गया कि यह विरोध जातिगत भेदभाव, एक दलित प्रोफेसर के साथ अन्याय और प्रशासन की असंवेदनशीलता के खिलाफ था। छात्रों ने न सिर्फ कक्षाओं को गोबर से लीपा, बल्कि प्रिंसिपल के घर तक जाकर वहां भी प्रदर्शन किया। दरअसल भारत में गोबर का उपयोग सदियों से पवित्रता, शुद्धता और स्वदेशी जीवनशैली के प्रतीक के रूप में होता आया है। लेकिन, इस मामले में इसका प्रयोग गहराई से व्यंग्यात्मक था। यह एक ऐसा प्रतीक था जो न केवल सत्ता की पवित्रता को उलट देता है, बल्कि यह दिखाता है कि छात्र अब विरोध के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर, सत्ता की भाषा को उसके ही प्रतीकों से जवाब दे रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय धीरे-

धीरे उस विचारभूमि से हटते जा

रहे हैं, जहां असहमति को

प्रोत्साहन मिलता था। आज यदि

कोई छात्र या प्रोफेसर सत्ता के

राष्ट्रविरोधी या विकास-विरोधी कहा जाने लगता है। कैंपस अब लोकतांत्रिक संवाद के केंद्र नहीं, बल्कि अनुशासन और डर के घेरे बनते जा रहे हैं। छात्रों के इस कदम को केवल असभ्यता कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि यह घटना उस निराशा और हताशा की उपज है, जो वर्षों से भीतर ही भीतर सुलग रही है। जब संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं. तो प्रतीकात्मक और चौंकाने वाले कदम ही एकमात्र विकल्प बनते हैं। निश्चित रूप से गोबर से दीवारें लीपना किसी भी संस्थान के लिए एक अनुशासनहीन हरकत मानी जाएगी, लेकिन यह भी सोचना होगा कि जब छात्र अपनी बात कहने के लिए इतना असामान्य तरीका अपनाते हैं तो समस्या केवल छात्रों में नहीं, व्यवस्था में भी है। वे किस हद तक खुद को असहाय और अनसुना समझते हैं, यह इस घटना से जाहिर होता है। यह विरोध न तो हिंसक था, न ही शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाला, लेकिन यह मानसिक और सांस्कृतिक असहजता पैदा करने

उद्देश्य भी था, लोगों को हिलाकर रख देना, ध्यान खींचना, और एक झटके में सत्ता की नकली गरिमा को धूल-गोबर में मिला देना। छात्रों का प्रदर्शन प्रिंसिपल के निजी घर तक पहुंचना न केवल प्रतीकात्मक था, बल्कि यह दशार्ता है कि छात्रों को अब संस्थागत दायरे में न्याय की उम्मीद नहीं रही। जब कॉलेज के भीतर के मंच निष्क्रिय हो जाते हैं, तो विरोध निजी दायरे तक पहुंच जाता है। यह खतरनाक संकेत हैं, न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने यह नहीं पूछा कि छात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं। किस घटना ने उन्हें इस हद तक पहुंचाया। किसने संवाद के रास्ते बंद किए। मीडिया अक्सर लक्षणों पर बहस करता है, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं जाता। सत्ता जब गाय और गोबर को संस्कृति का हिस्सा मानकर उन्हें नीतियों में शामिल करती है, जैसे गोबर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, पंचगव्य को चिकित्सा बताना, तब वह धर्मसम्मत होता है, लेकिन जब यही प्रतीक छात्रों के विरोध में आते हैं तो वे अश्लील और असभ्य

दोहरापन है। छात्रों का यह विरोध सत्ता के इस पाखंड की पोल खोलता है। यह दिखाता है कि सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग केवल सत्ता के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि आम जनता भी उन्हें विरोध के औजार बना सकती है। मान लीजिए, अगली बार छात्र प्रशासनिक आदेश को पवित्र मानकर उस पर गंगाजल छिड़क दें, तो क्या तब भी यह असभ्यता मानी जाएगी या यह संस्कृति के सम्मान में गिना जाएगा। जब प्रतीकों की राजनीति हो, तो प्रतीकों से ही जवाब देना सबसे तीखा व्यंग्य होता है और यही छात्रों ने किया। इस घटना के बहाने यह जरूरी हो गया है कि विश्वविद्यालयों में संवाद की संस्कृति को फिर से मजबूत किया जाए। छात्रों की आवाज को सुनने, समझने और मान्यता देने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। प्रोफेसरों और छात्रों के बीच विश्वास और सम्मान की नींव फिर से खड़ी की जानी चाहिए। किसी भी असहमति को देशद्रोह या अनशासनहीनता बताने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी। छात्रों को यह समझाना भी जरूरी है कि विरोध का तरीका ऐसा हो, जो व्यापक समाज में उनकी बात को सही तरीके से पहुंचाए, न कि केवल क्षणिक ध्यान आकर्षित करे। यह घटना एक प्रतीकात्मक चेतावनी है कि शिक्षा का मंदिर यदि सत्ता की चौकी बन जाए तो छात्र वहीं पर शुद्धि यज्ञ करने लगते हैं। गोबर का यह विरोध हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, वरना दीवारें ही नहीं, सोच भी गंधाने लगती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

देश में समाप्त होने की कगार पर पहुंचा नक्सलवाद

। छले छह दशकों से देश में चासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृहमंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आईं और चली गर्डं. मगर नक्सलवाद का नासर दिनों-दिन बढता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बडे हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था. जिसे लोग मानने को मजबर थे। मगर अब परिस्थितियां परी तरह बदल चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कई बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से

उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की

साउथ कैंपस स्थित एक कॉलेज में

मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले- बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, जबिक झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है. 9 से घटकर 6 रह गई हैं। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं। अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड संख्या अब घटकर 6 हो गई है। का लातेहार, ओडिशा का

नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों अनरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया

और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सिलयों को न्युट्रलाइज किया गया था। 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे. जबिक मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढकर 612 हो गई है। इसी प्रकार 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे, लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल

विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकडा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं. 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था, तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। इनमें मख्य रूप से आदिवासी थे।

Social Media Corner

है। उसे सार्वजनिक चौराहे पर न उधेड़ें। एक दिन वही दुनिया

आपके खिलाफ खडी हो सकती है।

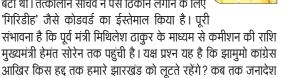
सच के हक में

विश्व पृथ्वी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां पृथ्वी जीवन को पोषित करती है और हमारे विकास और विकास के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम मां पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए अत्यंत सावधानी से परोपकार करें। मोदी सरकार सतत विकास के लिए

वैश्विक पहलों को आगे बढ़ा रही है, और अटूट प्रतिबद्धता के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। मैं उन संरक्षणवादियों की भी सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

(गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से करोड़ों रुपये के अवैध निकासी के आरोपी कैशियर सह अपर डिविजनल क्लर्क ने स्वीकार किया है कि कमीशन की राशि विभाग के तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन सचिव व अभियंताओं में बंटी थी। तत्कालीन सचिव ने पैसे ठिकाने लगाने के लिए



को अपमानित करते रहेंगे? (बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

सालभर में जाती है 3.3 लाख लोगों की जान

संकट एक आपात स्थिति का संकेत करता है। इस राष्ट्रीय आपदा से जुड़े आंकड़े हतप्रभ करने वाले हैं। केवल वर्ष 2022 में ही 1.68 लाख लोगों का जीवन सड़क दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ गया। यह संख्या दावोस, मोनाको या फिर भूटान की राजधानी थिंपू की आबादी से भी अधिक है। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, साल भर के दौरान देश में औसतन 3.3 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। यह संख्या आइसलैंड की आबादी से अधिक या द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों से भी अधिक है। स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत बहुत ऊपर है। विश्व की 11 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं, जबिक वैश्विक वाहनों का मात्र एक प्रतिशत ही देश में है। रोजाना 450 से अधिक भारतीय सडक दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खचाखच भरा एक एयरबस ए 380 विमान रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, पर यह मुद्दा सुर्खियों से गायब रहता है। इसमें जवाबदेही भी तय नहीं की जाती। त्रासद सड़क हादसों के और भी दुखद पहलू हैं। जैसे इनमें जान गंवाने वालों में 15 से 29 साल के लोग सर्वाधिक होते हैं। अक्सर ये अपने घर के कमाऊ लोग होते हैं

या फिर आगे कमाने का दारोमदार इनके ही

एक मौत इसी आयुवर्ग के लोगों की होती है। हादसों में आधी मौतें दोपहिया वाहनों या पैदल यात्रियों से जुड़ी होती हैं। यह तथ्य कमजोर बुनियादी ढांचे और सड़क पर सबसे कमजोर लोगों के प्रति सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता है। इन हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या किसी महामारी या आतंकी हमले की तुलना में भी कहीं ज्यादा है, लेकिन इस समस्या के समाधान की दिशा में न तो आवश्यक कानूनी पहल हो रही है और न ही सुधारों की शुरूआत। संक्षेप में कहा जाए तो सड़क हादसे मानवजनित सबसे बड़ी आपदा होने के बावजूद सबसे ज्यादा अनदेखी के शिकार हैं। सड़क हादसों से जुड़े संकट की जड़ों में घटिया इंजीनियरिंग, निम्न गुणवत्ता वाली परियोजनाएं, साइनबोर्ड न होना या भ्रामक साइनबोर्ड और इंजीनियरों एवं सलाहकारों की जवाबदेही का अभाव जैसे पहलू हैं। सरकार और एनएचएआई ने ब्लैक स्पाट चिह्नित करने और दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों में नए सिरे से डिजाइनिंग जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। सामान्य सड़कों से लेकर राजमार्गी तक समाधान दूर की कौड़ी बना हुआ है। कई जगह उचित साइनेज तो छोड़िए, लेन मार्किंग भी सही से नहीं हुई है। एक सवाल यह भी है कि जिन सड़कों पर संकेतक चिह्न हैं, क्या वाहन चालक वहां उनका

रत में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा कंधों पर होता है। सड़क हादसों में चार में से अनुपालन करते हैं। देखा जाए तो भारत में सड़कों का इन्फ्रास्ट्रक्कर उतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी सड़कों पर चलने को लेकर अनुशासनहीनता दिखती है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की राज्यों की प्रक्रिया का सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है। समय के साथ भारत में सड़कों की दशा और वाहनों की गति के मोर्चे पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन लाइसेंसिंग मानक कमोबेश जस के तस बने हुए हैं। जिस हिसाब से हाई स्पीड वाहन और एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़ी है उसके अनुपात में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समयानुकूल नहीं बन पाई है। देश के अधिकांश हिस्सों में ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर महज खानापूर्ति होती है, जिसमें एक सीमित हिस्से में गाड़ी को रिवर्स करने या उसे पार्किंग में लगाने जैसे कौशल परखे जाते हैं। तमाम आवेदकों को वास्तविक सड़क की परिस्थितियों, रात्रि ड्राइविंग, हाईवे मर्जिंग या इमरजेंसी रिस्पांस जैसी कसौटियों पर नहीं परखा जाता। इससे भी बदतर बात है कि तमाम लाइसेंस तो बिना किसी जांच-परख के ही जारी कर दिए जाते हैं जिसमें बिचौलिए रिश्वत के जरिए यह काम करा देते हैं। इस मोर्चे पर प्रशासनिक हीलाहवाली को दूर करना भी बहुत आवश्यक हो गया है। भारत की तुलना में विकसित देशों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत व्यापक एवं खरी है।

खुद को जख्मी करना

एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को हासिल कर से मुक्त का दर्जा खत्म कर देने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के न सिर्फ व्यापक विद्यार्थी समुदाय, बल्कि कॉरपोरेट अमेरिका एवं सैन्य-औद्योगिक परिसरों पर भी दूरगामी असर होंगे। ट्रंप प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि वह विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले को रोक देगा। विदेशी विद्यार्थी हार्वर्ड के विद्यार्थी समुदाय का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी गतिविधियों पर संघीय सरकार के इस आधार पर दखलंदाजी भरे नियंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सरकार भारी अनुदान मुहैया करा रही है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम की प्रत्यक्ष वजह हार्वर्ड और कोलंबिया में होने वाले गाजा युद्ध के खिलाफ तथाकथित वामपंथी, यहूदी विरोधी विरोध प्रदर्शन हैं, जिनकी छवि वामपंथी-उदारवादी की है। ऐसा जान पड़ता है कि ट्रंप प्रशासन अपने अमेरिका को फिर से महान बनाएं (एमएजीए) वाले आधार वर्ग को खुश करने में लगा है, जिसने पूर्वोत्तर के अभिजात वर्ग और उनके विश्वविद्यालयों के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से शिकायतें पाली हैं और जिसका उदाहरण आईवी लीग में मिलता है। ये संस्थान शैक्षणिक मानकों के मामले में वाकई श्रेष्ठ हैं, लेकिन हार्वर्ड उदार छात्रवृत्ति के जरिए विविध सामाजिक-आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों को दाखिला देता है। ट्रंप प्रशासन वैचारिक रूप से विविधता, समानता एवं समावेशन के सिद्धांतों का विरोध करता है और इस वजह से भी हार्वर्ड को निशाना बनाया गया है। लेकिन, हार्वर्ड के पास बहुत पैसा है और सत्ता के गलियारों में उसकी इतनी पकड़ है कि वह ट्रंप से ज्यादा वक्त तक टिक सकता है। ट्रंप द्वारा सरकारी अनुसंधान निधि में की गई कटौती से अलबामा जैसे घोर रिपब्लिकन समर्थक राज्यों के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालय भी प्रभावित हुए हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail: thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Wednesday, 23 April 2025

Nepal can ill afford return of monarchy

Public disaffection with the regime in Nepal, headed by Prime Minister Khadka Prasad Oli of the Communist Party of Nepal-United Marxist-Leninist (UML), primarily drives the rising popularity of the ex-King, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev. Oli's opponents accuse him of maladministration, crony capitalism and corruption. The large turnouts at pro-Gyanendra rallies gave the impression that the former King has a big following. Independent journalists who attended the rallies affirm that participants were not outright in favour of the monarchy but more against the performance of three parties — the Nepali Congress, the UML and the Communist Party of Nepal (Maoist Centre) — which have alternately constituted 14 governments in the country in the past 17 years, spending greater energy politicking rather than governing. Not one PM has served a full term of office.

The 2015 Nepalese Constitution declared the country as "an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive, democratic, socialism-oriented federal democratic republican state." A derogation from this would be difficult in the foreseeable future. In his comment on the "baseless enthusiasm of the royalists," former Tribhuvan University professor and ex-Ambassador to India, Lok Raj Baral, dismissed claims about the traction of the pro-monarchy protests.Oli has been in power for less than a year. Yet, popular ire against the present coalition government has taken the form of growing protests and demonstrations. Oli has embraced hyper-nationalism to bolster his popularity, unmindful that by doing so, he is fanning the same sentiments that work in favour of Gyanendra. Both Oli and Sher Bahadur Deuba, the head of the Nepali Congress and the coalition partner of the UML, appear to be losing their grip on their parties. It has become difficult for Oli to appear in public functions for fear of facing insulting sloganeering. Within the UML, which he seeks to control tightly, in the party elections such as the one recently held in Morang, the slate opposing the sponsored candidates scored an easy victory. The Nepalese intelligentsia has not appreciated cases of government high-handedness in forcing the resignation of the Tribhuvan University Vice Chancellor, Prof Keshar Jung Baral, and the removal of the head of the Nepal Electricity Authority, Kulman Ghising, attracting widespread disapproval. Both Baral and Ghising belong to Janajatis. Gyanendra's return as the head of state is not just supported by the die-hard Nepali royalists and supporters of the erstwhile 'party-less' panchayat system but also by reluctant republicans and closet monarchists. Another constituency favouring the monarchy are elements of the élite who are the most implacable opponents of federalism. Except for actor Manisha Koirala, the leaders of the pro-monarchy movement are not popular figures. Their political base is meagre.

Those at the forefront of the current agitation, such as Rabindra Mishra and Durga Prasai, the 'commander' of the Joint People's Movement Committee to restore the monarchy, do not enjoy a good reputation. It is perplexing that Gyanendra did not involve either the current Chairman of the Rashtriya Prajatantra Party, Rajendra Lingden, or Kamal Thapa, both of whom have previously served as Deputy Prime Ministers, and are the foremost respected advocates of constitutional monarchy and restoration of Nepal as a 'Hindu Rashtra', in the current agitation. But even the most ardent supporters of the ancien regime in Nepal believe that reinstating the King is a remote possibility. The Nepalese monarchy was conservative. It overturned the democratic Constitution of Nepal and introduced the panchayat system of government based on the pattern of 'guided democracy' introduced by Ayub Khan in Pakistan. It was a negation of democracy, with powers concentrated in the hands of the King.

Judiciary vs executive: 2 nations, 1 tense story

At the heart of both situations is one uncomfortable truth: the executive doesn't like being told what to do, especially not by unelected judges.

The Constitution is a compact. Power is distributed. The judiciary doesn't govern and the executive doesn't adjudicate. That's the theory. The practice, as we're seeing today in both India and the United States, is messier.

Two Vice-Presidents — India's Jagdeep Dhankhar and America's JD Vance — have taken on their respective judiciaries, not with subtlety but with full-throated public attack. In doing so, they have brought a long-simmering institutional friction to the surface. This isn't just another round of power play. It's a warning shot.

India's VP Dhankhar is unhappy with the Supreme Court. He says it's acting like a "super Parliament" by issuing timelines to the President for deciding on state Bills. In his view, judges are overstepping their mandate. They interpret the law, they don't issue executive deadlines.

Speaking to Rajya Sabha interns, he lamented that only the President takes an oath to "defend" the Constitution — others, including judges, merely promise to "abide" by it. For him, that difference matters. It shapes who can tell whom what to do. He didn't stop there. He accused the judiciary of operating without accountability - no FIRs in corruption cases involving judges, no asset disclosures and unlimited use of Article 142 to issue sweeping directions. He called Article 142

a "nuclear missile against democratic forces." The message was clear: Courts have gone too far, and it is time for Parliament to push back. Dhankhar's frustration stems from a broader narrative — one where the judiciary is often seen stepping into a vacuum left by a gridlocked or dominant Parliament. But when courts start filling gaps left by the executive, the executive doesn't like it. And Dhankhar, a lawyer-turned-legislator turned VP, has taken it upon himself to push back. On the other hand, US Vice-President JD Vance had a public meltdown over a court order that embarrassed the Trump administration. A federal appeals court blasted the government for its "shocking" failure to bring back Kilmar Abrego Garcia, a wrongly deported father detained in El Salvador's prison, CECOT. The court's opinion, written by Reagan-appointee Judge J Harvie Wilkinson, didn't mince words. He accused the administration of acting without due process, ignoring court orders and flirting with lawlessness. He even invoked Eisenhower's example from the desegregation era to show what real executive fidelity to the courts looks like. Vance didn't like that. He took to social media,

fuming that someone with a "valid deportation order" shouldn't be in the US, despite the government itself admitting that the deportation was a mistake. His comments fit a pattern — Trump-era officials showing disdain for judges who stand in their way, mocking rulings and talking about impeachment of "activist"

These aren't isolated incidents. They reveal a pattern of

institutional confrontation that's getting sharper. In India, Dhankhar's criticism is part of a larger narrative



that accuses the judiciary of being unelected and unaccountable, yet wielding vast power. The executive The idea of revisiting Article 142 — so often used by courts resents the court stepping into legislative and administrative matters — from electoral reforms to gubernatorial delays. In the US, the judiciary is facing outright defiance. Courts have ordered the government to act. The government has shrugged. Abrego Garcia remains in El Salvador despite a SC ruling. Instead of compliance, we've heard insults — from calling judges "radical lunatics" to dismissing court directions as political games. At the heart of both situations is one uncomfortable truth: the executive doesn't like being told what to do, especially not by unelected judges. In both countries, the courts are not staying silent. India's SC has, by and large, chosen the route of reasoned restraint. It speaks through its judgments, sometimes scathing, but always measured. Its message: where Parliament fails, we must step in. Not because we want to rule, but because someone has to uphold the Constitution.

In the US, the judiciary is more direct. Judge Wilkinson's opinion reads less like a judgment and more like a philosophical defence of constitutional governance. He

warns of "anarchy" if the executive keeps ignoring court orders. He reminds readers that due process is not optional — even for someone accused of being a gang member. Even when elections give the executive a strong mandate, it doesn't mean the Constitution takes a holiday. Judge Wilkenson rules, "This is a losing proposition all around. The Judiciary will lose much from the constant intimations of its illegitimacy, to which by dent of custom and detachment we can only sparingly reply. The Executive will lose much from a public perception of its

lawlessness and all of its attendant contagions. The Executive may succeed for a time in weakening the courts, but over time history will script the tragic gap between what was and all that might have been, and law in time will sign its epitaph...."Thus, courts are not claiming perfection. But they are asserting their role — as guardians of the law, not servants of political convenience.

In India, Dhankhar has hinted that constitutional amendments may be necessary. Article 145(3), which requires Constitution Bench rulings on substantial constitutional questions, was drafted when the court had only eight judges. Today, with 30-plus, Dhankhar argues the threshold needs to

to do "complete justice" — is also gaining traction among those in power. There may be attempts to clip its wings.

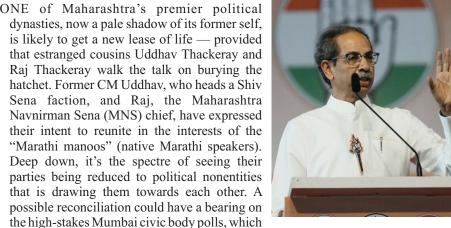
In the US, reform debates are less about amending the Constitution and more about judicial ethics, term limits and court expansion. But the deeper issue is executive accountability. If court orders can be ignored without consequence, then any talk of reform becomes mootThis isn't just elite squabbling between institutions. This is about the nature of democracy itself. If the executive can dodge accountability — by calling judges names, ignoring orders or complaining about interference — then the balance of power collapses. If courts overstep consistently — by becoming de facto legislators — they risk losing their legitimacy.

It's a delicate dance. But it needs both partners.

In both India and the US, the judiciary has become the last resort for many. Citizens turn to courts when government machinery fails, Parliament is gridlocked or basic rights are under threat. This burden is not one that courts always welcome — but it is one they often bear.

Thackeray thaw

Uddhav-Raj reunion can be mutually beneficial



are expected to be held this year. Raj had quit the Shiv Sena two decades ago after a fallout with his uncle and party founder Bal Thackeray, who could not resist the urge to elevate son Uddhav up the party ladder. His



fledgling MNS made a good start by winning 13 seats in the 2009 Assembly elections; however, the party has been pushed to the sidelines over the years, and it drew a blank in last year's polls. Still, Raj continues to be an

influential leader, especially because of his strident 'Marathi first' agenda. No wonder Deputy Chief Minister Eknath Shinde paid him a visit at his residence last week. Shinde, who broke ranks with Uddhav in 2022 and now heads the 'official' Shiv Sena, is desperate to ensure his party's success in the civic polls. He knows that an under-par show will further weaken his position vis-a-vis the dominant BJP. Known for striking the best bargain for himself, Raj will probably keep his options open for as long as he can.

Much will depend on Uddhav's efforts to win over his cousin. He has already sounded a note of caution that nothing should be done to help

the 'thieves', an allusion to the ruling Mahayuti that includes the BJP, Shinde's Sena and Ajit Pawar's NCP. Amid the tug-of-war over Balasaheb's legacy, the Thackeray duo would be well advised to close ranks.

Deported by error: Garcia case and its echoes in India

He ended his story by telling me: "I don't want to die here. I want to be buried in my homeland." The Indian authorities never agreed, as far as I know, to his return.

The ongoing Abrego Garcia deportation case in America illustrates the helplessness of individuals who sink into the quicksands of bureaucracy and/or disputes between state organs for no fault of their own. The fate of persons who inadvertently get caught in the meshes of adversarial inter-state relations is, perhaps, worse. I

know of some of these Kafkaesque situations involving Indians. This case revived these memories. But first, a brief assessment of the implications of the Garcia case for Trump's America.At 16, Garcia from El Salvadore entered the US illegally in 2011. He later married a US national. An immigration court ruled in 2019 that he could not be deported from the US. That decision stands. Yet, the US immigration authorities deported him to El Salvador, where he was imprisoned. Garcia's wife approached the Federal District Court of Maryland. The US authorities admitted in court hearings that Garcia's deportation was because of an "administrative error." The court ordered that he be brought back immediately.

The Trump administration went to the Supreme Court, arguing that Garcia was a member of MS-13, a designated foreign terrorist gang, and his return to the US would constitute a

public safety threat. Ignoring this aspect, the Supreme Court ordered that the government should "facilitate" Garcia's return and keep the District Court informed of its actions. It also directed the District Court to respect that foreign policy was in the government's domain. The Trump administration has no intention of seeking Garcia's return. Indeed, El Salvador's President Nayib Bukele, after meeting Trump in Washington on April 13, told reporters that he had no intention to release Garcia.

The District Court is soldiering on, but it is likely to succeed. The fact is that Trump is destroying the institutional balance which is the foundation of the US system. Now, to two Indian cases of persons who faced unforgiving bureaucracies determined to uphold national interest!In the early 1990s, a Belgian nun called



the Indian Mission in Islamabad from Lahore that two young Indians were in her church. The Mission told her to send them to Islamabad. They were received on arrival and debriefed. At the same time, the Pakistani Foreign Ministry was informed because they would have monitored the call from Lahore. The two boys said that they were sailors employed in the UAE. Their vessel had sunk off the Iranian coast. They were rescued and put in an Iranian detention centre. One day, they were reach Quetta and took a train to Lahore. One of them was from Goa and the other from Bihar. The Pakistani Foreign Office directed that they be sent to a police station, where they were arrested, charged and imprisoned for two years. The Pakistani newspapers

> reported that two R&AW agents had been arrested!

> The Goa boy's mother lived in Mumbai and visited the Ministry of External Affairs occasionally to seek its intervention for his early release. My colleagues treated her with empathy. I spoke to the Pakistan DHC, pressing that they were innocent boys deserving sympathy. He found their story unbelievable. After serving their sentences, they were released. The mother brought her son to Delhi to meet us because she told him that the MEA had been a great support. What the son told me was this.In addition to the two, three more were rescued from the vessel by the Iranians and all five boys were pushed into Pakistan. All five reached Lahore and got into two

tongas, which got separated. The two in one tonga went to a church for help; the Goanese was a Christian. The Pakistani priest there panicked and called the nun.

asked him about what happened to the other three. After some reluctance, he said "Sir, they went to Karachi by train and being sailors, went to a seamen's association's office near the port. They related their story to its officebearers who believed them. They were put on a boat bound for Mumbai and are now living safely there."

pushed across the border into Pakistan. They managed to He also told me that the Pakistani sailors had taken an oath from them that they would not contact any Indian official just as they had not informed any Pakistani official. I pleaded with him to inform one of them that I would like to meet the three. He said that he would pass on the message. The three never broke their oath!

The second case is that of an Indian who was one of Abu Dhabi ruler Sheikh Zayed's drivers. The Director of the ruler's office called me and asked why he was being denied a visa. This was 1980 and I was at our embassy in Abu Dhabi. The driver, who was in his sixties, came to see me and related his story.

He said that he reached Dubai in 1945 from Kerala. Some years later, he fell ill and was being taken on a dhow to Kerala, but as his condition worsened, the dhow dropped him in Karachi. He was hospitalised and when he recovered, he wanted to go home quickly, but he had no identity papers. He was advised by some locals that he should get Pakistani papers and an Indian visa for that was the quickest way for him to get home. He did.

In Kerala he got married, threw away his Pakistani passport, got an Indian one and returned alone to Dubai. After a few years, he returned to India on his Indian passport, but a neighbour told the police that he had earlier come on a Pakistani passport. He was taken into custody and deported to Dubai. For over two decades, he had not been able to go to India while his family remained there. He ended his story by telling me: "I don't want to die here. I want to be buried in my homeland." The Indian authorities never agreed, as far as I know, to his return. Nowadays, there are heart-rending cases of young persons of both countries who cross the India-Pakistan border inadvertently and spend years in prison unless compassionate border security officials do not refer their cases to the police but quietly return them to the other side. But such compassion is rare.

Wednesday, 23 April 2025

Is the Rs 500 note in your wallet real or fake? Look out for this small typo



New Delhi. Is the Rs 500 note in your wallet genuine or fake? That's the question the Ministry of Home Affairs (MHA) is now urging citizens to ask, after issuing a high-priority alert warning about the circulation of "high-quality" counterfeit currency in India. The MHA has flagged a surge in fake Rs 500 notes that are so well-made, even experienced handlers are finding it hard to detect them, reported.

These counterfeits reportedly match the original in print, ink, and paper quality—making them dangerously convincing at first glance.

HOW TO IDENTIFY?

The only visible clue lies in a subtle but telling typo: the phrase "Reserve Bank of India" has been misspelt as "Resarve Bank of India," with an 'A' replacing the 'E'.Officials familiar with the alert have described this error as "very subtle," and likely to escape notice unless checked carefully. Describing the situation as "high importance," the MHA has circulated this alert to key agencies such as the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Financial Intelligence Unit (FIU), Central Bureau of Investigation (CBI), National Investigation Agency (NIA), and Securities and Exchange Board of India (SEBI), along with all major banks and financial institutions.

To aid detection, a photograph of the suspected counterfeit note has also been distributed to banks and enforcement agencies. These institutions have now been placed on high alert.

With counterfeiters getting more sophisticated, the government is urging everyone—from cash handlers at banks to everyday citizens-to stay alert. The smallest spelling oversight could be the only thing standing between fake and real money. So the next time you're handed a Rs 500 note, take a moment. Look closely, especially at the spelling.

PM Modi AC Yojana 2025: Govt To Provide Free 5 Star AC? Here's The Truth Behind **Viral Post**



New Delhi. A news is going viral in the social media that says the government is all set to provide free air conditioners under PM Modi AC Yojana 2025 for which 1.5 crore 5-star ACs have been prepared.

The message, that has been widely circulated in the social media says PM Modi AC Yojna 2025 will be launched in May and will provide free 5 star ACs for people who will apply ASAP. Due to this, there will be huge shortage of ACs in India as 1.5 crore have already been prepared. The message further says that after the government accepts request, people will get their ACs within 30 days.

Busting the fake message, The Press Information Bureau (PIB) has confirmed that the above claim is fake. No such scheme providing free 5- Star Air Conditioners has been announced by the MinOfPower" A post being widely shared on social media claims that under a new scheme 'PM Modi AC Yojana 2025', the Government will provide free 5-star air conditioners and 1.5 crore ACs have already been prepared," PIB Fact check has

FM Sitharaman Invites Global CEOs, Investors To Join India's Growth Story

San Francisco. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met global CEOs, pension fund managers and other institutional investors here, and discussed the opportunity for collaboration in the domain of energy and sustainability, the Rs 1 lakh crore (\$12 billion) corpus private sector-driven research, development, and innovation scheme, and GIFT-IFSC, among others.

In the presence of Finance Secretary Ajay Seth and Vinay Mohan Kwatra, Ambassador of India to the US, the Finance Minister listened to their views on the reforms pursued by the Indian government, and gave feedback and observation on the existing policy framework.

They spoke about their keen interest and commitment for a deeper and broad-based investment collaboration between the US and India and shared feedback on how to further facilitate and enhance the investment experience.

The Union Minister thanked the participants for their valuable feedback and suggestions. In her one-onone meetings with top CEOs, FM Sitharaman discussed opportunities in the fields of AI, Cloud and digital infrastructure. Jonathan Siddharth, CEO of Turing, expressed his desire to see India at the forefront of AI revolution and spoke about working in the domain of AI with India and through Indian contributors to create a sovereign model that can serve as a template for the world. The Finance Minister highlighted policy framework that has been put in place by India for AI, and encouraged Siddharth to explore opportunities for collaboration and fruitful engagement.

China's gold ATM melts jewellery and sends money in 30 minutes. Check here

The gold ATM, which is set up in China's Shanghai, melts gold, checks its purity and weight, and transfers the value to your bank account.

New Delhi. China's gold ATM is grabbing attention not just in Shanghai, but around the world. This gold ATM, which is set up in Shanghai, melts gold, checks its purity and weight, and transfers the value to your bank account. The ATM, run by China's Kinghood Group, accepts



and with at least 50% purity. It melts the gold, checks its quality and weight, and then transfers the equivalent value straight to the seller's bank account within 30 minutes. No paperwork or ID is needed.

gold items weighing over three grams Thanks to rising gold prices, people are

lining up to cash in their old jewellery, reports mention. The demand is so high that users now need to book a slot to use the machine. Reports say all appointments are booked till May, reflecting its strong demand, as per

In one demonstration, a 40-gram gold chain fetched 785 yuan (around Rs 9,200) per gram. The total payout? Over 36,000 yuan, or Rs 4.2 lakh, credited to the seller's account in half an hour, according to the publication. Harsh Goenka, Chairman - RPG Enterprises, wrote on X, "Gold ATM in Shanghai: Drop your jewellery, it checks purity, melts it, calculates value, and credits your account instantly."

He added that this technology may become a threat to gold lenders in India. "If this comes to India, traditional gold lenders might need a new business model. Transparency in. Exploitation out," Goenka mentioned. Meanwhile, this gold ATM in China is more than just a fancy machine; it's a sign of changing times. With rising gold prices and growing interest in quick, transparent transactions, the machine signals a move towards smarter, paperless solutions that blend traditional wealth with modern

Flipkart plans to relocate holding company to India from Singapore

BENGALURU. Walmart-owned ecommerce major Flipkart to shift its domicile back to India from Singapore. This comes ahead of its potential IPO plan, and the ecommerce giant is the latest company to do 'reverse flipping' after PhonePe, Razorpay, Groww and Zepto.In a statement, Flipkart said, this strategic decision reflects our deep and unwavering commitment to India and its remarkable growth."We are inspired by the Government of India's strong vision and proactive initiatives in fostering a thriving business environment and ease of doing business, which have significantly shaped our journey. This move represents a natural evolution, aligning our holding structure with our core operations, the vast potential of the Indian economy and our technology and innovation-driven capabilities to foster digital transformation in India,"

"As a company born and nurtured in India, this transition will further



enhance our focus and agility in serving our customers, sellers, partners, and communities to continue contributing to the nation's growing digital economy and entrepreneurship. We are excited by the opportunities ahead and reaffirm our long-term confidence in India's future," the ecommerce firm added. Earlier this year, quick commerce firm Zepto completed its reverse merger from Singapore to

Another Walmart-backed company PhonePe in 2022 moved its domicile to India from Singapore and its investors had paid Rs 8,000 crore in taxes to

Last year, fintech start-up Groww moved its parent entity, Groww Inc, from Delaware to Bengaluru. According to reports, it paid about Rs 1,340 crore tax for domicile shift.

Google settles smart TV case by paying Rs 20 cr

NEW DELHI. The Competition Commission of India (CCI) has given a nod to the Rs 20.24-crore settlement proposal of Google in the Android Smart TV case. Apart from the settlement amount, Google will provide a standalone licence for the Play Store and Play Services for Android smart TVs in India, thereby removing the requirement to bundle services or impose default placement conditions. It will also waive off the need for a valid Android Compatibility Commitments (ACC) for devices shipped into India that do not include Google apps. OEMs can now sell and develop incompatible Android devices without violating Google's agreement.

The case is related to allegations that Google misused its dominant position by enforcing restrictive agreements on OEMs, including compulsory bundling of the Play Store with Android TV OS and preventing the use or creation of rival forked Android versions through its anti-fragmentation agreements.

A complaint in this regard was filed against Google LLC, Google India Private Limited, Xiaomi Technology India Private Limited and TCL India Holding Private Limited.

The gist of the allegation was that Google misused its dominant position by enforcing restrictive agreements on OEMs, including compulsory bundling of the Play Store with Android TV OS and preventing the use or creation of rival forked Android versions through its Anti-Fragmentation Agreements. These practices allegedly blocked market access, curbed competition, and placed unrelated obligations on Original Equipment Manufacturers (OEMs), ultimately stifling innovation and violating provisions of Section 4 of the Act. The Commission formed a prima facie view that Google has contravened various antitrust provisions and ordered an investigation into

The investigation concluded that Android Smart TV OS has a dominant position in the relevant market of 'licensable Smart TV device operating system in India' and Google Play Store is in a dominant position in the 'Market for App Store for Android Smart TV OS in India'.

It found that Google's agreements-Television App Distribution Agreement (TADA) and Android Compatibility Commitments (ACC)—executed together, imposed unfair terms by requiring the pre-installation of its full app bundle Google TV Services, preventing OEMs from developing or using Android forks, and hindering innovation. These agreements extended across entire device portfolios and included the tying of services like YouTube with the Play Store, strengthening Google's market dominance and breaching several provisions of Section 4 of the Act.

Amazon, Walmart's Flipkart may gain from US push in India trade deal: Report

NEW DELHI.Amazon and Walmart could emerge as key beneficiaries of the evolving India-US trade talks, with Washington expected to press New Delhi for greater access to the country's \$125 billion ecommerce market, the Financial Times reported on

Citing industry executives, lobbyists, and US officials, the report said the Trump administration is gearing up to push Prime Minister

Narendra Modi's government for a level playing field in the e-commerce space—one that allows American giants like Amazon and Walmart more flexibility than current rules permit.India currently imposes restrictions on foreign-owned online



retailers, including bans on holding inventory and selling directly to consumers. Domestic players like Reliance, by contrast, face no such constraints, giving them an edge in both online and offline retail.

The trade talks are expected to cover a broad range of sectors-from food

and automobiles to digital commerce. While specific US demands on e-commerce have not been disclosed, negotiators are hoping to iron out a deal within the 90-day tariff truce announced by President Trump on April 9 for key trading partners, including India.

US Vice President JD Vance also met with Prime Minister Modi on Monday, signalling a diplomatic push toward sealing the agreement.

Neither Amazon nor Walmart have commented on the developments, and India has yet to outline its position publicly. However, New Delhi is seen to be prioritising the deal to stave off potential tariffs and preserve its export competitiveness.

RBI allows minors above 10 to operate bank accounts

Banks have been given the flexibility to set the rules for these accounts based on their own risk management policies. This includes setting limits on the amount of money that can be kept in such accounts and deciding on the terms and conditions.

New Delhi. The Reserve Bank of India (RBI) has announced new rules that allow children above the age of 10 years to open and operate their own savings or term deposit bank accounts independently. This rule applies to all commercial banks and cooperative banks, including primary (urban) cooperative banks, state cooperative banks, and district central cooperative banks. The central bank released a circular on Monday explaining the updated rules. This move comes after a review of the older guidelines, which were first issued many years ago. The RBI has now simplified and combined the rules for opening and running

deposit accounts for minors. MINORS CAN OPEN ACCOUNTS



ONTHEIROWN

"Minors of any age may be allowed to open and operate savings and term deposit accounts through his/her natural or legal guardian," said RBI in its release. As per the new rule, any minor, regardless of age, can open a savings or term deposit account through their natural or legal guardian. However, minors who are at least 10 years old can now open and manage these accounts on their own, if they wish to do so.

Banks have been given the flexibility to set the rules for these accounts based on their own risk management policies. This includes setting limits on the amount of money that can be kept in such accounts and deciding on the terms and conditions. These terms must be clearly shared with the young account

RULES WHEN AMINOR TURNS 18

Once a minor turns 18 and becomes an adult, the bank must collect fresh account operating instructions and a new specimen signature. If the account was earlier operated by a guardian, the bank must also confirm the account

balance. Banks have been asked to take action ahead of time and inform the account holders well in advance so that there is no delay in updating the account details after the account holder turns 18. Banks are also free to offer more banking

services to minor account holders. These can include internet banking, ATM or debit cards, and cheque books. However, these services can be offered only after the bank reviews its risk management rules and confirms that the products are suitable for young users.

RBI has made it clear that accounts of minors, whether operated independently or by a guardian, must not be allowed to go into overdraft. This means the account balance should always remain positive. Banks must ensure that there is no loan or negative balance in such accounts.

Banks are required to follow all Know Your Customer (KYC) rules when opening accounts for minors. This includes doing proper checks while opening the account and continuing to verify the account over time. These rules are part of the Master Direction on KYC issued by the RBI in February 2016, which has been updated from time to time.All banks must update or create their internal policies in line with the new RBI guidelines by July 1, 2025.

Shocks the conscience: Delhi High Court raps Ramdev over 'sharbat jihad' remarks

The Delhi High Court slammed Baba Ramdev for his communal remarks against Hamdard's Rooh Afza, calling them "indefensible" and "shocking." Ramdev had accused the company of funding madrasas and mosques, prompting legal action from Hamdard.

Twist In Air Force Officer's

Assault Case In Bengaluru

the video went viral.

New Delhi. In a twist, after a couple serving in the Indian

Air Force was assaulted in Bengaluru, a new video has

emerged showing one of them thrashing the alleged

attacker. Both sides attacked each other, cops have

confirmed, suggesting it was not one-sided violence.

Deputy Commissioner of Police (East) Devraj D

clarified that it was not a case of Kannadigas vs non-

Kannadigas, as claims emerged on social media when

The development comes after Wing Commander

Shiladitya Bose posted a video, with blood on his face

and neck, narrating the incident. The accused has also

filed a counter-complaint against the Air Force officer.

Yesterday, Wing Commander Bose alleged that "A bike

came from behind and stopped our car... the guy started

abusing me in Kannada. When they saw the DRDO sticker on my car and said 'You DRDO people', and they

abused my wife and me, I couldn't bear it. The moment I

got out of my car, the biker hit me with a key on my

forehead, and there was blood."Read more: "God Help

Us": Air Force Officer Assaulted, Wife Abused In BengaluruThe officer's wife, Squadron Leader

Madhumita Bose, was taking her husband to the airport

early morning from DRDO Colony in Bengaluru's CV Raman Nagar.The video went viral, but initially it was

unclear what triggered the assault. A new video has

emerged showing the accused, Vikas Kumar, and the officer attacking each other on a pavement in Bengaluru. The accused, in a green neon jacket, was

pushed by the officer, who grabbed his neck while his

wife was trying to stop him. Bystanders on the footpath

intervened to stop the fight, talking to Wing Commander

Bose. The accused was seen calling someone, after

Hit Job Disguised As Crime Of

Passion: Delhi Cops Crack

Woman's Murder Case

which the officer punched him.

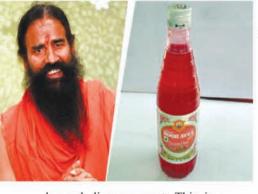
New Delhi. The Delhi High Court on Tuesday expressed strong displeasure with Baba Ramdev's recent comments that used terms such as "sharbat jihad" to target the popular drink Rooh Afza. The "indefensible" comments shock the "conscience of court", the Delhi High Court said as it heard a plea by Following the remarks, the Rooh Afza-maker Hamdard against Baba Ramdev's comments. The comments in question were made earlier this month when Baba Ramdev launched Patanjali's rose sharbat. During the launch, Baba Ramdev said, "There's a company that gives you sharbat, but the money it earns is used to construct madrasas and mosques." While he did not name Hamdard or Rooh Afza, his comments were widely understood to have been directed at the popular drink."If you drink that sharbat, madrasas and mosques will

be built. But if you drink this [referring to Patanjali's rose sharbat], gurukuls will be built, Acharya Kulam will be developed, Patanjali University will expand, and the Bharatiya Shiksha Board will grow."

company moved to the High Court against Baba Ramdev.

"Just like there is love jihad, this is also a kind of sharbat

jihad. To protect yourself from this sharbat jihad, this message must reach everyone," Baba Ramdev had also said, prompting Hamdard to file a petition against the comments.Senior Advocate Mukul Rohatgi, who appeared for Hamdrad in the Delhi High Court on Tuesday, said, "This is a case which is shocking, which goes



beyond disparagement. This is a case of creating a communal divide, akin to hate speech. It will not have protection from the law of other sharbat brands to "toilet cleaners," saying, "Protect your family and innocent children from the poison of toilet cleaners being sold as soft drinks and sharbat Jihad. Choose only Patanjali

sharbat and juices," the brand declared on social media.

This isn't the first time Baba Ramdev and Patanjali have come into controversy. Over the past two years, Patanjali and its founders have faced several legal challenges due to their advertisements. The matter escalated nationally after the Indian Medical Association (IMA) filed a plea against Patanjali Ayurved, leading the Supreme

Court to impose a temporary ban on its ads and issue contempt notices over misleading claims.

defamation."He also compared In January, a Kerala court issued bailable warrants against Baba Ramdev and Acharya Balkrishna after they failed to appear in a case concerning misleading ads by Divya Pharmacy. A similar case was also registered in Kozhikode.

10 cyclists killed, 21 hurt in three months in national capital

NEW DELHI. In the first three months of 2025, Delhi has witnessed 28 road accidents involving cyclists, claiming 10 lives and injuring 21 others, official data showed on Sunday.

According to the data shared by the police, the city recorded 18 cases of simple accidents and 10 related to fatal accidents till March 31, 2025. The data further mentioned that a total of 149 accidents — 96 simple and 53 fatal — were reported last year, in which 53 people lost their lives and 106 were injured. Similarly, 30 cyclists died in 2023 and 118 were injured in 141 accidents — 112 simple and 29 fatal. The data also showed that the fatality in 2022 was 43 per cent higher than in 2023. A total of 48 cyclists died in 2022 and 134 were injured in 170 accidents. In 2021, the data showed that 45 cyclists lost their lives, while 123 were injured in 147 accidents.

In one of the incidents in March, a 19-year-old Delhi University student, who worked as a newspaper vendor, died when his bicycle was hit by a vehicle in Rohini. The deceased was identified as Rishal Singh, a resident of Budh Vihar. The incident took place at a red light near the RTO office on the dividing road between Rohini Sectors 15 and 16. Rishal, who was pursuing his graduation, used to work as a newspaper distributor in the morning. He earned around Rs 12,000 monthly to fund his education and support his family.

The police data also showed that 1,551 people died in 5,657 accidents across six ranges — Central, Northern, Eastern, New Delhi, Southern, and Western — last year. The Northern range witnessed the highest number of deaths, with 398 fatalities in 1,305 accidents, followed by the Western range with 343 deaths in 1,247 accidents, Eastern range with 237 deaths in 894 accidents, Central range with 214 deaths in 683 accidents, New Delhi with 191 deaths in 692 accidents, and Southern range with 168 deaths in

Delhi HC to hear 52 cases again after Justice Varma's transfer over cash row

NEW DELHI. The Delhi High Court on Monday announced that 52 pending cases, earlier assigned to the Division Bench of Justice Yashwant Varma and Justice Harish Vaidyanathan Shankar, will now be heard again from the beginning. These are cases where no formal orders had been passed earlier and will now be taken up by the current roster bench."It is hereby notified for the information of all concerned that the following matters, previously listed before the Division Bench comprising Justice Yashwant Varma and Justice Harish



Vaidyanathan Shankar, in which a next hearing date had been assigned but no orders were drawn, shall be re-listed and heard afresh before the roster bench," the court said in its official notice. This move follows the recent transfer of Justice Yashwant Varma from the Delhi High Court to the Allahabad High Court. His transfer has sparked controversy due to serious allegations against him. His name came up in an investigation after semi-burnt sacks allegedly containing large amounts of cash were found at his residence during a fire on March 14.

Schools refusing to promote pupils of Classes 6, 7 violation of RTE: Parents

NEW DELHI. Parents and activists have alleged that several prominent schools in the national capital allegedly held back students in classes 6 and 7, in stark violation of the Right to Education Act (RTE) of 2009. The Ministry of Education's Department of School Education and Literacy notified guidelines on 'Examination and Holding Back in Certain Cases' in December 2024, after the 2019 amendment to RTE Act.Educationist and advocate Ashok Agarwal, president of the All India Parents' Association (AIPA), said, "The amended rules allow schools to detain students in classes 5 and 8 only, that toom after giving them additional opportunity for re-examination within two months from the date of declaration of results. There was no detention policy till Class 8 before the amendment. However, the government



revised the act to include a provision for detention in Class 5."Several parents complained over the issue, alleging that schools asked their children to either repeat a year in classes 6 or 7, or take a school-leaving certificate. "My son is in Class VI and we have been told that if he does not clear the re-exam scheduled in May, he will not be promoted to the next class. But norms say that students cannot be detained in classes other than 5 and 8. My son couldn't score well due to bad

Ganguly, former chairman of the Central Board of Secondary Education, the RTE Act, the National Education Policy, and the National Curriculum Framework prohibits any school from refusing promotion to a student in classes 6 and 7. Amendment enables schools to hold

health this year," a Gurugram-based parent said. According to Ashok

back Class 5, 8 students

In December 2024, the Centre had amended the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Rules, 2010, giving state governments power to conduct regular exams for students in classes 5 and 8, with the provision to hold them back if they fail. This marked a departure from the long-

standing 'no-detention' policy, a cornerstone of the educational framework since the enactment of

Hospistals must report heat illness: Delhi government

NEW DELHI. The Delhi government on Monday unveiled a comprehensive heat action plan to combat the increasing health risks associated with extreme heat. In a significant move, all hospitals have now been directed to mandatorily report cases of heat-related illnesses (HRIs), a step aimed at strengthening surveillance and enabling timely medical interventions.

Inder the new guidelines, all government healthcare facilities across the city (Primary Health Centres, Community Health Centres, district hospitals and medical colleges) will be required to set up dedicated wards and earmark beds specifically for patients suffering from heatstroke.

As per the action plan, these wards are to be located in cooler areas of the hospitals and equipped with essential supplies like ice packs, thermometers, blood pressure apparatus, oral rehydration salts (ORS), intravenous fluids, and cooling equipment such as fans and air conditioners.



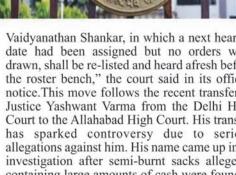
The action plan also includes instructions for hospitals to stock crucial medicines including lorazepam and diazepam, and ensure the availability of silver sulphadiazine cream, calamine lotion, and other skin treatments to manage heat-related skin issues.

Ambulances have also been equipped with cold water and ice packs for emergency cooling during transport. Health experts said heat-related illnesses are largely preventable but can prove fatal if not identified and managed quickly."Heat stroke and heat exhaustion are the two most dangerous conditions. Older adults, young children, and people with chronic

medical conditions are at high risk for heat-related illness and death," said Dr Vikram Jeet Singh, Senior Consultant, Internal Medicine, Aakash Healthcare.

Summer heat waves can present serious risks to human health in the form of heat-related illnesses, including heat rashes, fainting, heat exhaustion and heat stroke If not managed immediately, they can lead to serious and potentially fatal

outcomes. Conditions like heat exhaustion can rapidly progress to heat stroke, which is a medical emergency. Without prompt treatment, heat stroke can cause damage to vital organs such as the brain, heart, kidneys, and muscles. This can result in long-term complications, permanent disability, or even death. Delayed intervention also increases the risk of shock and multiorgan failure," the doctor said. Dr Singh recommended the public to monitor their hydration levels. "A good rule of thumb is looking at your urine. If it's relatively clear, you're reasonably well-hydrated," the doctor added.



The Supreme Court launched an inquiry into the matter and has kept the findings sealed. The report is not accessible to the public or to Parliament. A three-judge panel has been set up by the top court to investigate further. Justice Varma was known for handling major constitutional and corporate law cases. His sudden transfer and a private swearing-in ceremony at the Allahabad High Court, instead of a formal public event, have added to the

Situation gone from bad to worse: Supreme Court on child trafficking

..The court also issued a stern reminder to the authorities about the urgency of tracing the missing children and arresting those behind the racket.

NEW DELHI. The Supreme Court on Monday expressed grave concern over the deteriorating state of child trafficking in the national capital, observing that the "situation seems to have gone from bad to worse."A bench comprising justices J B Pardiwala and R Mahadevan made the observations while hearing a case related

to the trafficking of several newborns in Delhi's Dwarka area. The court was interacting with a Delhi Police inspector entrusted with investigating the case.

The bench pulled up the police over their failure to apprehend the alleged kingpin, Puja and directed the station concerned to take immediate and effective steps to arrest her and recover three missing infants. "The situation seems to have

gone from bad to worse," Justice Pardiwala said, while expressing concern over the alleged involvement of parents in trafficking."You never know where these children will land up. In the case of a girl child, you know where she lands.'

The court also issued a stern reminder to the authorities about the urgency of tracing the missing children and arresting those behind the racket. "You have to find these

missing children at any cost and arrest the kingpin," the bench said during the hearing.On April 15, the apex court had dealt with a similar case involving interstate child trafficking. In that matter, it had cancelled the bail of 13 accused, emphasising that the "cry of the collective for justice, its desire for peace and harmony" could not be trivialised.

In the present case, the court reiterated its commitment to ensuring the protection and welfare of trafficked children. It

directed the government to admit all rescued children into schools under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, and ensure continued support for their education.

The court also reflected on the broader patterns of child trafficking across India, noting that the problem is not only widespread but evolving.

An overall analysis of trafficking patterns across states reiterates the prevalence of trafficking in

large numbers, with the number of cases sharply rising with time," the bench observed. Of particular concern, it said, was the emergence of previously unknown trafficking factors.

Changing trafficking patterns have brought changes in traffickers, their modus operandi, their manipulation of the victims and their understanding of time limitations in the criminal justice system," the top court added.

Delhi. The murder of a 20-year-old woman in Delhi's GTB Enclave, which had first appeared to be a spurned lover's crime of passion, has now been found to be a cold-blooded hit job. Sayra Parveen was shot dead on April 14 when she stepped out after dinner. Her bloodied body with two bullet injuries was found on a road when her family started looking for her.Police scanned the footage of the area's CCTV cameras and

identified a suspect. He was later arrested. Rizwan told the police that he wanted to marry Sayra, but she had rejected his proposal and asked him to stay away. Upset over this, he shot her dead. On the face of it, the murder appeared to be a spurned lover's attack on a woman. But further questioning revealed a sinister plan linked to another crime. About four months back, some men were heckling Sayra in Nand Nagri in East Delhi. A passerby, Rahul, saw this and rushed to help. An altercation broke out between Rahul and those harassing Sayra. This face-off turned physical and Rahul was killed. In the investigation that followed, Sayra was named a key witness in the murder case.

Prashant Gautam, Deputy Commissioner of Police for Shahdara, said Rahul's uncle Kishan blamed Sayra for Rahul's death. He believed that she did not get into an altercation that day, Rahul would not have intervened and would not have been killed.

According to police, Kishan and Firoz also suspected Sayra was becoming friends with some of the accused and may turn hostile in court and her statement may weaken the case. They plotted her murder and started looking for someone who could pull the trigger. This is where Rizwan came in. The 20-year-old has told the police that he wanted to be a "dada" of the area and took up the job to prove himself. Rizwan first befriended Sayra on social media and started chatting. They then decided to meet. April 14 was their third meeting. This time, Rizwan spotted an opportunity and shot Sayra dead.also arranged a pistol and four bullets for the

Justice will be done': FBI **Director Kash Patel on** arrest of terrorist Harpreet Singh in US

NEW YORK. Kash Patel, FBI Director, has assured that justice will be done, following the arrest of Gangster-turned-terrorist Harpreet Singh in the US.

Singh alias Happy Passia alias Jora, wanted in connection with multiple terror attacks across Punjab and who is alleged to have collaborated with Pakistan's ISI and Khalistani group BKI, was arrested in the US on April 18 by the Federal Bureau of Investigation (FBI) and US Immigration and Customs Enforcement's Enforcement and Removal Operations in Sacramento."CAPTURED: HARPREET SINGH, part of an alleged foreign terrorist gang here illegally in the United States, who we believe was involved in planning multiple attacks on police stations both in India and the United States. @FBISacramento conducted the investigation, coordinating with our partners locally as well as in India," Indian-American Patel said in a post on X on Monday."Excellent work from all, and justice will be done. The FBI will continue finding those who perpetrate violence no matter where they are," the first Indian-American to lead the premier law enforcement agency of the United States said in the post.Singh is suspected to have collaborated with Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) and the Khalistani terrorist group Babbar Khalsa International (BKI)."He had been evading capture by using untraceable burner phones and encrypted applications. This case reinforces the importance of international cooperation in apprehending those who threaten global security," FBI Sacramento said on April 18.In January, India's National Investigation Agency (NIA) announced a cash reward of Rs 5 lakh on gangster Harpreet. Harpreet, a native of Ajnala tehsil in Amritsar, Punjab is wanted in a case of a hand grenade attack on a house in Chandigarh.

Singh is an absconder in the case registered on October 1, 2024, in connection with the hand grenade attack carried out on a house in Sector 10/D, Chandigarh.

Gaza rescue service dismisses Israeli probe into killing of medics as a 'fabricated investigation

CAIRO. The main Palestinian rescue service in Gaza on Monday condemned Israel's probe into the killings of 15 medical workers last month, calling it a "fabricated investigation." The army announced the results of its investigation on Sunday, saying it had found "professional failures" and dismissing a deputy commander in what it described as an accident.

A total of 15 people were killed in the March 23 incident - including eight medics with the Palestinian Red Crescent Society, six members of the Hamas government's Civil Defense unit and a United Nations staffer. Troops bulldozed over the bodies along with their mangled vehicles, burying them in a mass grave. U.N. and rescue workers were only able to reach the site a week later. In a statement, the Palestinian Red Crescent Society said the investigation underscores "the occupation's persistence in shielding the truth from the world."

It accused Israel of making "fallacious allegations" that medical rescue teams are part of Hamas and asked why Israel continues to detain a paramedic who survived the attack."We call on the international community to abstain from validating the results of the occupation's fabricated investigation," it said.

Israel at first claimed the medics' vehicles were acting suspiciously and did not have emergency signals on when troops opened fire. But the army later backtracked after cellphone video recovered from one medic showed the ambulances had lights flashing and logos visible as they pulled up to help another ambulance that earlier came under fire.

The military said six of those killed were Hamas militants, but has given little evidenced to support the claim. The shootings outraged many in the international community, with some calling the killings a war crime.

Pope's frequent calls to Catholic church made him revered figure in warbattered Gaza

GAZA.DEIR AL-BALAH, Gaza Strip: In the last 18 months of his life, Pope Francis had a frequent evening ritual: He would call the lone Catholic church in the Gaza Strip to see how people huddled inside were coping with a devastating war. That small act of compassion made a big impression on Gaza's tiny Christian community and was why he was remembered at his death Monday as a beloved father figure in the beleaguered territory.

'I was deeply saddened. He was our biggest supporter after God," said Suheil Abu Dawoud, a 19-year-old Christian in Gaza. Francis "always healed our wounds and asked us to be strong," he said. "He was always praying for us.'

In his last public appearance, Francis called for a ceasefire between Israel and the Hamas militant group. A fervent advocate of interfaith relations, he also urged Hamas to release the dozens of Israeli hostages it is holding and condemned growing global

antisemitism. In his Easter message, Francis expressed his "closeness to the sufferings of Christians in Palestine and Israel and to all the Israeli people and the Palestinian people."While noting the growing antisemitism, he added: "I think of the people of Gaza and its Christian community in particular, where the terrible conflict continues to cause death and destruction and to create a dramatic and deplorable humanitarian situation."

Jury picked for US actor Harvey Weinstein MeToo retrial: 7 women, 5 men on panel

Opening statements expected Wednesday, final alternates pending Jury includes diverse professionals from Manhattan

Weinstein faces retrial after 2020 conviction overturned

New York. A jury of seven women and five men has been picked for Harvey Weinstein's #MeToo rape retrial, a more female panel than the five women and seven men who convicted the onetime Hollywood honcho at his first trial five years ago. Opening statements aren't expected until Wednesday, as prosecutors and defence lawyers still need time to finish picking the last of six alternate jurors those who step in if a member of the main panel can't see the trial through.Drawn from Manhattan's jury pool, the 12 members of the main jury include a physics

researcher, a photographer, a dietician, an investment bank software engineer, a retired city social worker, and more. After nine jurors were picked last week, three others and five alternates were tapped Monday during a marathon fourth day of jury selection. They and other prospective jurors were quizzed about their backgrounds, life experiences and various other points that could relate to their ability to be fair and impartial about the highly publicised case."You

may hear sexual allegations here of a salacious nature - graphic, perhaps. Would hearing that indicate that Mr. Weinstein must be guilty?" defence attorney Mike Cibella asked one prospective juror.

The woman, who ultimately was chosen, answered no.

Potential jurors had been questioned privately about their knowledge of the case



people were excused after those queries behind closed doors.Still, when the questioning moved into open court, prosecutor Shannon Lucey sought assurances that prospective jurors could put aside any position or feelings they had about the #MeToo movement. It was catalysed in 2017 by a raft of sexual misconduct allegations against Weinstein, then a high-flying movie producer and one of the most powerful people in his industry. and opinions about Weinstein, and some "Is there anyone who is going to think of the

movement and think, 'OK, that's just something that I have to keep in the back of my mind when I'm deciding this case'? Everyone can put that aside?" Lucey asked a group of 24 possible jurors. All indicated they could do so. Weinstein is being tried again on rape and sexual assault charges after New York's highest court last year overturned his 2020 conviction and 23-year prison sentence. The Court of Appeals found that his trial had been tainted by improper rulings and prejudicial testimony. Weinstein, 73, has pleaded not guilty and denies raping or sexually assaulting anyone. The retrial involves charges that he raped an aspiring actor in a Manhattan hotel room in 2013 and committed a criminal sex act by forcing oral sex on a movie and TV production assistant in 2006. He also is charged with another criminal sex act count, based on an allegation from a woman who was not a part of the original trial. She alleges that Weinstein forced oral sex on her at a

Columbia activist's wife gives birth, says husband denied release to be present

world. Noor Abdalla, the wife of jailed Columbia University graduate and Palestinian activist Mahmoud Khalil, has announced the birth of their son. On Monday evening, Noor released an statement saying, "I welcomed our son into the world earlier today without Mahmoud by my side. Despite our request for ICE to allow Mahmoud to attend the birth, they denied his temporary release to meet our son. This was a purposeful decision by ICE to make me, Mahmoud, and our son suffer."Mahmoud is currently being held in a detention centre in Louisiana, over 1,000 miles away from the New York hospital where Noor gave birth. The Department of Homeland Security denied his request to temporarily release him for the birth. Mahmoud was only able to witness this experience via phone. Abdalla, a 28-year-old New



York dentist, and her newborn baby boy, both are in good health.

NOOR VOWS TO FIGHT FOR JUSTICE

Noor has been vocal about her husband's case since his arrest. She stated that the government is targeting Mahmoud due to his activism in favour of Palestinian rights. Abdalla, who is an Americanborn citizen and raised in Michigan. Her parents immigrated to the US from Syria approximately 40 years ago.

The Trump administration is trying to silence those who speak up for Palestinian rights," she said earlier this month. "We will not be silenced. We will persist, with even greater resolve, and we will pass that strength on to our children and our children's children - until Palestine is free."Despite welcoming her child without Mahmoud, Noor says she won't stop fighting for her husband's freedom. "I will continue to fight every day for Mahmoud to come home to us," she said. "I know when Mahmoud is freed, he will show our son how to be brave, thoughtful, and compassionate, just like his dad."Khalil was detained on 8 March on the basis that he is deemed to be a threat to US foreign policy. Earlier this month, an immigration judge ruled that Khalil can be deported from the United States.

Mark Carney urges strong mandate to counter Trump, liberals leading April 28 polls

Canadian Prime Minister Mark Carney, ahead in polls in the run-up to an April 28 election, renewed calls on Monday for voters to give him a strong mandate to dea with US President Donald Trump's tariff threat. Carney says Trump's tariffs and talk of annexation pose a huge threat and mean that Canada needs to reduce its reliance on the United States and restructure its economy."We need a government that has a strong mandate, a clear mandate. We need a government that has a plan that meets the moment," Carney said during a campaign event in Charlottetown in the Atlantic province of Prince Edward Island. The 60-year-old ex-central banker, who had no prior political experience before running to become Liberal leader earlier this year, billed himself as "someone who knows how to negotiate ... (and) how to manage a crisis."

The Liberal platform, which promises additional spending of around Canadina \$130 billion over the next



Downtown Houston Courthouse shootout leaves deputy, suspect wounded

Man opens fire on deputies at Houston courthouse Veteran deputy injured but saved by bulletproof vest Suspect armed with two handguns, shot by deputies

UPDATED A downtown Houston

courthouse turned into the scene of a midday shootout on Monday when a man armed with handguns opened fire on deputies, wounding a veteran officer before being shot himself.The incident occurred around 12:20 p.m. near the Harris County Family Law Center, after deputies responded to reports of a man seen with a handgun walking from the nearby Civil Courthouse, reports Associated Press."He ran from us initially and then turned around and took a shot at one of our officers - and they, of course, returned fire," said Harris County Precinct 1 Constable

Alan Rosen during a news

conference. Assistant Chief Deputy

Carl Shaw of the Precinct 1 Constable's Office said deputies began pursuing the man when he was spotted with a weapon near the courthouses in downtown Houston - an area that typically sees thousands of visitors daily for court hearings and jury duty. The suspect, who has not yet been

identified, was armed with two handguns when he was shot by veteran deputy with 30 years in law enforcement, was shot on her left side during the confrontation but avoided life-threatening injuries thanks to her bulletproof vest."She's tough. That investigation.

vest saved her life," Rosen said. "We're incredibly thankful." Both Jones and the suspect were taken to area hospitals and were listed in stable condition as of Monday afternoon. Authorities say the suspect was being charged with one court of aggravated assault of a peace officer, but more

> expected against him. No other injuries were reported. Five deputies were involved in the encounter with the suspect, and investigators are trying to determine how many of them fired their weapons, Rosen said. At least

charges were

one building near the shooting had a bullet go through one of its windows. deputies, Rosen said. Sheila Jones, a The injured deputy has been in law enforcement for 30 years and

previously worked for the Harris County Sheriff's Office. The identity and motive of the suspect remain under

four years, predicts that the 2025/26 deficit will be Canadian \$62.3 billion, far higher than the Canadian \$42.2 billion forecast in December.

Carney replaced Justin Trudeau, who had been in power for more than nine years and was the focus of opposition attacks about inflation, high immigration levels and a housing crisis. The official opposition Conservatives had been 20 points ahead at the turn of the year but now trail the Liberals.A rolling three-day Nanos poll released on Monday put the Liberals on 43.7 per cent public support with the Conservatives on 36.3 per cent. The left-leaning New Democrats, who compete with the Liberals for the center-left vote, trailed at 10.7 per

If repeated on election day, that would give the Liberals a majority of the 343 seats in the House of Commons.

Elections Canada said a record 2 million people had cast their ballots in the first of day of advance voting on Friday, which was a national holiday. Around 28 million Canadians are registered to vote. Voter turnout in federal elections from the 1950s to the early 1990s ranged between 70 per cent and 80 per cent, but it has gradually declined. In the 2021 election, only 62.3 per cent of eligible voters cast ballots. Ipsos Public Affairs CEO Darrell Bricker said the advance polls could indicate that overall turnout will be higher, or merely reflect parties' efforts to boost early voting.

Harvard sues Trump administration to stop the freeze of more than \$2 billion in grants

Harvard's suit called the funding freeze "arbitrary and capricious," saying it violated its First Amendment rights and the statutory provisions of Title VI of the Civil Rights Act.

BOSTON. Harvard University announced Monday that it has filed suit to halt a federal freeze on more than \$2.2 billion in grants after the institution said it would defy the Trump administration's demands to limit activism on campus. In an April 11 letter to Harvard, the Trump administration had

called for broad government and leadership reforms at the university and changes to its admissions policies. It also demanded the university audit views of diversity on campus and stop recognizing some student clubs. The administration has argued universities allowed antisemitism to go unchecked at campus protests last year against Israel's war in Gaza. Harvard President Alan Garber said the university would not bend to the demands. Hours later, the government froze billions of dollars in federal funding. Students, faculty and members of the Harvard University community rally, Thursday, April 17, 2025, in Cambridge, Mass.Trump administration takes aim at Harvard's international students and tax-exempt status"The Government has not — and cannot identify any rational connection between antisemitism concerns and the medical, scientific, technological, and other research it has frozen that aims to save American lives, foster American success, preserve American security, and maintain

America's position as a global leader in innovation," said the lawsuit, filed in Boston federal court."Nor has the Government acknowledged the significant consequences that the indefinite freeze of



billions of dollars in federal research funding will have on Harvard's research programs, the beneficiaries of that research, and the national interest in furthering American innovation and progress," it added. Harvard's suit called the funding freeze "arbitrary and capricious,"

saying it violated its First Amendment rights and the statutory provisions of Title VI of the Civil Rights Act. Within hours, the White House lashed back."The gravy train of federal assistance to institutions like

Harvard, which enrich their grossly

overpaid bureaucrats with tax dollars from struggling American families is coming to an end," White House spokesman Harrison Fields said in an email Monday. "Taxpayer funds are a privilege, and Harvard fails to meet the basic conditions required to access that privilege."For the Trump administration, Harvard presents the first major hurdle in its attempt to force change at universities that Republicans say have become hotbeds of liberalism and antisemitism. A

part of that is targeting research funding which has fueled scientific breakthroughs but has become an easy source of leverage for the Trump administration.In its letter earlier this month, the administration told Harvard to impose tougher discipline on protesters and.

NEWS BOX

IPL 2025: KL Rahul helping plot plans against LSG, reveals Vipraj Nigram

New Delhi Delhi Capitals' Vipraj Nigam has said that the team will be using KL Rahul's insights for the game against Lucknow Super Giants on Tuesday, April 22. Rahul was the captain of LSG till last season and guided them to the playoffs in 2022 and 2023. Most of the players in the current, including the likes of Nicholas Pooran and Avesh Khan played under the 33-year-old over the past few seasons. This will be the first time Rahul will be playing against LSG since leaving the franchise after not being retained ahead of the IPL 2025 auction. Speaking at the prematch press conference, Nigam said that Rahul's knowledge of the LSG players will be helpful and they do discuss about it during team meetings.

Not specifically for this match, but I do get advice from seniors in every game on how to perform better. Regarding Rahul bhaiya, yes, he helps, especially since he's played with some players who were part of Lucknow last year and are still with them this year. So in our team meetings, we definitely discuss that—it really helps when someone has that insight about the opposition's bowlers and



batters," said Nigam. Speaking about Faf du Plessis' availability, Nigam said that the South African batting is recovering well but the final call will be taken by the team management."He is recovering well but the final call will be taken by the management," said Nigam.

'Consider myself an all-rounder'

Speaking about his role in the team, Nigam said that he considers himself to be an allrounder and wants to make contributions with bat and ball whenever required.

'I consider myself an all-rounder. I have to make contributions with the ball and also with the bat whenever required," said Nigam.Nigam also talked about the pressure of playing in front of his home crowd and said that it just adds up when playing infront of family and coach.

Steve Waugh on Rohit Sharma's future as Test captain: Can't be complacent or relaxed

New Delhi Former Australia cricketer Steve Waugh has said that it's up to Rohit Sharma to decide if he wants to play Test cricket for India. Rohit's Test future is in question following the team's failure to qualify for the World Test Championship (WTC) Final for the first time, under his leadership. India lost back-to-back series against New Zealand and Australia, which crushed their hopes for a third consecutive appearance in the summit clash. To make matters worse for Rohit, his poor form in the red-ball format has also raised questions about his place in the team. Recently, Waugh was asked about Rohit's Test future in the Indian team and the legendary Australian captain replied that it's



up to him to solve that problem. He further said that the India captain needs to look at himself in the mirror and ask if he still has the hunger to play the longest format for his country."It is totally up to him. He is the only one who can solve that problem. He has got to look himself in the mirror and say, do I still want to be captain or play for India? Am I committed? Am I putting enough time and effort into it? It is a privilege and an honour to play for your country. You can't be complacent or relax," Waugh told PTI.Furthermore, Waugh was asked about the criticism South Africa is facing for qualifying for the WTC final without playing against top teams and playing less number of matches. The legendary batter gave the example of how people complained about India playing in Dubai during ICC Champions Trophy 2025 and said that South Africa did well in the number of matches they played and are fully deserving to be in the final."There's always complaints. In Champions Trophy, India played a neutral ground in Dubai and people complained

LSG vs DC, IPL 2025 Preview: Predicted XI, team news and Lucknow pitch conditions

- **→** Delhi Capitals are on the second spot on the table with ten points
- Lucknow Super Giants are on fifth spot with ten points as
- **→** Delhi beat Lucknow in their opening game of the season

New Delhi. Lucknow Super Giants (LSG) are set to take on Delhi Capitals (DC) in Match 40 of the Indian Premier League 2025 (IPL 2025) on Tuesday, April 22 at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow. Lucknow are coming into the game after registering a thrilling win over Rajasthan Royals (RR) by two runs in the previous fixture. Avesh Khan held his nerve in the final over and successfully defended eight runs to help his team register their fifth win of the season.LSG have



performed exceptionally under the form as they've won five out of eight matches to be on the fifth spot on the points table. In the batting department, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh and Aiden Markram have been in phenomenal form. On the other hand, Shardul Thakur, Digvesh Rathi, Avesh Khan and Ravi Bishnoi have troubled the

batters with the ball.

leadership of Rishabh Pant despite his poor All in all, Lucknow look like a well-balanced team in the ongoing season and will aim to LSG vs DC: TEAM NEWS climb higher on the points table with a win over DC. Especially after losing their season opener against them by one wicket. Delhi Capitals are coming into the game, having suffered just their second loss of the season against Gujarat Titans.In a rare failure of

their bowling attack, Delhi allowed Gujarat to chase down the target of 204. However, they're enjoying a golden run under the leadership of their new skipper, Axar Patel, who's impressed with his shrewd leadership. DC batting lineup has fired collectively with KL Rahul being the top performer. On the bowling front, Kuldeep Yadav and Mitchell Starc are topping the charts being successful in applying the pressure in different stages of the match. Hence, both teams have a wellrounded squad for the upcoming encounter, which promises to be another exhilarating clash after Delhi beat Lucknow by one wicket in their first

LSG vs DC: HEAD-TO-HEAD

The two teams are even in terms of head-tohead records with both teams having won three matches each out of the six encounters between them. They're also tied with one win each at the Ekana Stadium.

Fast bowler Mayank Yadav has made rapid progress in his fitness but it remains to be seen if he will be available for the clash. For Delhi, Faf du Plessis isunlikely to be available for the fixture after injuring himself while fielding against RCB.

Harsha Bhogle breaks silence on missing KKR games: Inappropriate conclusions drawn

New Delhi Decorated commentator Harsha Bhogle has dismissed rumours suggesting he is not part of the IPL 2025 commentary panel for Kolkata Knight Riders' home games at Eden Gardens, Kolkata. Bhogle clarified the reason behind his absence from Monday's match between KKR and Gujarat Titans, stating that "inappropriate conclusions" were being drawn regarding his absence from the commentary box.Reports on Monday claimed that Harsha Bhogle and former New Zealand cricketer-turned-commentator Simon Doull had been red-flagged by the Cricket Association of Bengal (CAB), which had allegedly requested the BCCI not to assign them to KKR's home fixtures. According to the PTI news agency, this purported stance from the CAB came in response to criticism from Bhogle and Doull regarding Eden Gardens pitches prepared by CAB curator Sujan Mukherjee during IPL



2025. Taking to X (formerly Twitter), Bhogle clarified that he had been assigned just two matches in Kolkata this season, and had missed the second one due to personal reasons. Neither Bhogle nor Doull were part of the commentary panel for Monday's match between KKR and GT at Eden Gardens."There are some inappropriate conclusions being drawn about why I wasn't at yesterday's game in Kolkata. Quite simply, it wasn't on the list of matches I was down to do! Asking me would have resolved the issue. Rosters are done before the tournament starts. I was rostered for two games in Kolkata. I was there for the first and an illness in the family prevented me from being at the 2nd," Bhogle wrote on Tuesday, April 22.Both Bhogle and Doull, speaking to Cricbuzz, had criticised the Eden Gardens curator for not providing pitches that suited the home team's strengths. Doull had even suggested that KKR should consider relocating their home games away from Kolkata if they continued to receive pitches that did not aid their chances of winning.KKR captain Ajinkya Rahane and head coach Chandrakant Pandit have also expressed disappointment over the lack of

spinner-friendly.

Djokovic returns to Madrid seeking his 100th tour-level title

MADRID. Former champion Novak Djokovic has returned to the Madrid Open for the first time in three years in hopes of achieving his 100th tour-level title.

Djokovic is seeded fourth in the same half of the draw as second-seeded Carlos Alcaraz, the home favorite who arrives at the Caja Magica this week with fitness concerns after reaching consecutive clay-court finals.

The 37-year-old Djokovic, a three-time champion in Madrid, hasn't played in the Spanish capital since losing to Alcaraz in the 2022 semifinals, their first meeting.Djokovic won his 99th title last August at the Paris Olympics. He has lost four finals since then, most recently last month in Miami. The 100-title club features only Jimmy Connors (109) and Roger Federer (103). Over the last two weekends, Alcaraz has won the Monte Carlo Masters and lost in the Barcelona Open final, where he needed treatment on his upper right leg



"I'm confident it won't affect me in Madrid," he said. "That's what happens when you play so many matches and have so few days to rest. It's so demanding, and you have to give 100% every day. Having played a tournament like Monte Carlo and arriving in Barcelona with few days to adapt is really tough."Alcaraz said fellow Spaniard Rafael Nadal, a five-time winner in Madrid, wrote to him after the Barcelona final to encourage

him and say he hoped he wasn't injured. 'I how at the feet of Rafa because of what he did week after week," Alcaraz said. "You have to respect that."

Alexander Zverev, No. 2 in the world after winning in Munich at the weekend, was the top seed in Madrid and Taylor Fritz was the third seed. Defending champion Andrey Rublev was the seventh seed.

Djokovic has a 30-9 record in Madrid, with titles in 2011, 2016 and 2019. He beat his coach Andy Murray in the 2016 final.

Alcaraz won Madrid in 2022 and 2023.

Sabalenka leads women's drawThe women's draw has 29 of the top 30 players. No. 15 Barbora Krejcikova is missing because of an injury.Top-ranked Aryna Sabalenka seeks her fourth final appearance in Madrid in five years. She won the tournament in 2021 and 2023, and lost last year's final to Iga Swiatek, the second seed this week.

What is Ashwin doing Former World Cup winner slams CSK veteran



Former India opener and selector K Srikkanth was not impressed with veteran spinner R Ashwin's bowling performance during Chennai Super Kings' (CSK) nine-wicket loss against Mumbai Indians at the Wankhede Stadium. "What is Ashwin doing? He has turned

completely defensive," Srikkanth said on his YouTube channel 'Cheeky Cheeka'.

'He is not looking to take wickets. It's like, 'Let me just get through these four overs.' He never went for wicket-taking. Just bowling safe."What was the idea of picking Ashwin today? To get two wickets

and win the match. But what did he do? He bowled safely in the powerplay."It didn't matter to CSK at all. MI (Mumbai Indians) were also sensible, taking singles off him. You have to understand the match situation, the IPL situation - and bowl accordingly," Srikkanth said.R Ashwin has picked up only five wickets in seven outings this season.

At the start of the tournament, Srikkanth had questioned how CSK had used Ashwin. He said: "With regards to Ashwin, don't drop him, but stop him from bowling in the powerplay. Between the 7th and 18th over, he can be effective. With Jadeja and Noor Ahmad, they can easily bowl 10 overs at least."

Srikkanth also maintained that the season for CSK is over and they should start building for the next season."Dhoni has already started talking about next season. That means he is pretty frustrated with this team's performance. He was right in saying that the guys have to own up and do something fantastic. Where CSK lost was in the auction itself. If you select players like Sam Curran, Overton, Tripathi, Hooda, how can you win matches?" Srikkanth said.

IPL 2025: Rajasthan Royals face match fixing allegations after shocking loss vs LSG

- Rajasthan Royals failed to score nine runs in last over vs
- **⊸**They earlier lost a close game against Delhi Capitals as well
- The Sanju Samson-led side is on eighth spot on points table

New Delhi Rajasthan Royals (RR) are facing allegations of match fixing following their shocking loss against Lucknow Super Giants (LSG) in Match 36 of the Indian Premier League 2025 (IPL 2025). Jaideep Bihani,

Rajasthan Cricket Association (RCA) ad hoc committee convener, has alleged that the team was involved in some foul play, raising questions about their loss in the close encounter. Chasing a target of 181 runs, the Sanju Samson-led side required just nine runs to win in the final over, having six wickets in hand. However, much to everyone's surprise, they ended up losing the match by two runs as LSG's Avesh Khan successfully defended the score for his team with his exceptional death bowling. However, the loss didn't go down well with Jaideep Bihani, who questioned how the team lost on its home ground after needing just a few runs to win the encounter. In an interview given to News18 Rajasthan, Bihani mentioned the controversial past of the Rajasthan Royals in the IPL as their players were caught in spot-fixing in 2013.Moreover, the franchise owner Raj Kundra was also caught in betting, leading to



their ban for two seasons in 2016 and 2017 along with Chennai Super Kings (CSK). Hence, he demanded an investigation into the matter, urging the BCCI and other agencies to take stock of the situation. Apart from that, Bihani has also alleged that the Rajasthan Cricket Association was sidelined from overseeing the hosting of the IPL due to baseless excuses. The ad hoc committee has been appointed by the state government in Rajasthan. After analysing our work, we were given an extension for the fifth time. During our tenure, we've conducted all

competitions successfully right from the district level to the national level. However, as soon as the time for hosting IPL came, the Sports Council took control of it. For IPL, the BCCI had first sent a letter to RCA only. The excuse given by Sports Council and RR was that we don't have an MOU from Sawai Mansingh Stadium. If MOU is not there, so what? Aren't you paying Sports Council for every match?," Jaideep Bihani said in the interview.

Earlier, Rajasthan also failed to score nine runs in the last over against Delhi Capitals (DC) having seven wickets in hand and eventually lost the match in the super over. Following their fourth successive defeat, they are now teetering at the eighth spot on the points table with two wins from eight matches having four points to their name. They will next take on Royal Challengers Bengaluru (RCB) on 24th April at M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru.

When

Wednesday, 23 April 2025





obby Deol recently revealed he was "really upset" after being abruptly removed from Jab We Met, despite initiating its early development with Kareena Kapoor Khan and director Imtiaz Ali. Amid this, an old interview of Imtiaz Ali is doing the rounds on social media. While speaking to The Lallantop, Imtiaz recalled why Bobby was left out of the film.Imtiaz Ali said, "Jab We Met ko Bobby Deol ke saath banane ka plan kar raha tha. Start kari picture but usko kuch aur offers mil rahe the, kuch bade directors ke saath. Toh voh wait kar raha tha. Keh raha tha ki iske baad kar lenge, uske baad kar lenge. Toh, karte karte ek aisa waqt aagaya jo mujhe laga ki ab yeh theek nahi lag raha."

Imtiaz added, "Bohot waqt beet chuka hai kyuki vaise bhi, 5 saal tak maine ek hi film ki hai. Uske baad bhi ek do saal tak main kuch nahi kar raha tha. Toh matlab financially and even in life, you want to do things. Toh maine bola Bobby yeh film nahi banate hain. Let us decide this today. Let us shake our hands ki film nahi banate kyuki humara ek doosre ke saath sahi nahi rahega."

mtiaz's interview has resurfaced amid Bobby Deol's recent revelation of feeling hurt. Speaking to Instant Bollywood, Bobby shared how he first discovered the script while watching a rush print of Socha Na Tha, which Imtiaz was directing with Bobby's cousin Abhay Deol. Impressed, Bobby urged Imtiaz to write a film for him, which eventually evolved into Jab We Met. "I tried really hard to make that film (Jab We Met) happen; I reached out to a lot of people," he said. Bobby claimed that he played a major role in bringing the production house Shree Ashtavinayak Cine Vision on board. The producers, he said, were interested in working with him but hesitant about backing Imtiaz, who was still relatively new at the time. Bobby pushed for the collaboration and successfully convinced them to give the director a shot. He also reached out to Kareena Kapoor Khan through a contact to offer her the lead role, but she initially declined. Preity Zinta was also approached, but turned it down, saying she would consider it at a later time.

Anshul Garg Asks Fans To Suggest Title For Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa's 'Intense Love Story'

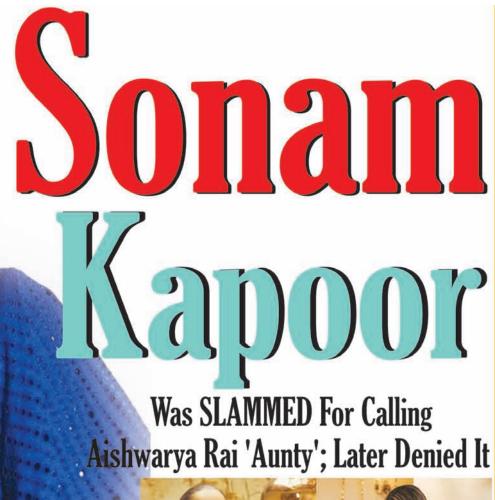


arshvardhan Rane and Sonam Bajwa starrer upcoming romance film has already gone on floors, with debutant producer Anshul Garg on board for the project. Taking to his Instagram handle, Garg reached out to his fans to suggest title ideas for the film, which he described as an "intense love story." Garg also shared a picture with the lead actors along with other team members from the sets of his film. While Harshavardhan and Sonam could be seen dressed up in their respective characters, director Milap Zaveri also joined the frame for the picture. "Suggest me a name for this intense love story! Reading all comments!" Anshul Garg wrote in the caption.

Fans wasted no time sharing their reactions, along with a couple of suggestions for the film's title. One wrote, "Diwaniyat will be a very beautiful story, and this unique team and its actors will make the story much more interesting," while another added, "Raqeeb or Bekhudi? Just going by the current title." It seems to me that Deewaniyat is a good name for a love story ... But if you think about it, you can come up with more options," a fan added. A section of fans even suggested that Garg name the film Sanam Teri Kasam 2. With multiple reports touting the film title as Deewaniyat, the makers are yet to officially confirm the same.

Last week, Desi Movies Factory announced the film, revealing the debut of music producer Anshul Garg into the world of cinema. "With seetis, taalis, masala, music, romance, and mass mayhem, we present Anshul Garg's 'Production No. 1,' co-produced by Raghav Sharma, written and directed by Milap Milan Zaveri, starring Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa, and cowritten by Mushtaq Shiekh!" the makers mentioned. The film will be released in 2025. The team has started shooting for the film in Mumbai, with Garg dropping the first pictures on his Instagram handle.

Speaking on the same, Garg expressed his views on his debut film as a producer. "I have always believed in stories that connect emotionally, and I believe this film is the right project to begin the journey. It's a film where music plays a central narrative role—the kind of story where songs don't just support the plot, they carry it forward," he said, as quoted by The Times of India. Harshvardhan Rane also shared how Anshul Garg's vision has been "clear" for the film, which he describes as inspiring.



n 2009, Sonam Kapoor said something about Aishwarya Rai that

n 2009, Sonam Kapoor said something about Aishwarya Rai that sparked widespread outrage among fans. In an interview, she referred to Aishwarya, then 36, as "aunty" and reasoned it out by saying that the actor has worked with her father, Anil Kapoor. Her comment didn't sit well with Aishwarya's fans, and she was brutally trolled. After the backlash, Sonam denied making any such comment altogether and praised the Devdas actor.

Why did Sonam Kapoor call Aishwarya Rai 'aunty'?

It so happened that back in the day Aishwarya was replaced as the brand ambassador of a popular beauty brand by Sonam. Some reports stated that it was Aishwarya who had backed off, giving the opportunity to the Delhi 6 actor. When asked about it, Sonam referred to Aishwarya and called her "aunty from another generation". This statement drew widespread flak. Soon after, Sonam was asked about her "aunty" remark. She defended her statement and said, "Aish has worked with my dad so I have to call her aunty na!" She referred to Aishwarya co-starring with Anil Kapoor in films such as Taal, Hamara Dil Aapke Paas Hai, and others. That too, created trouble for the actor.

However, she soon went on deny that she would never call Aishwarya "aunty". In another interview, Sonam said, "It's all gossip. I never said any of that. I don't want to remark on it anymore. A lot has been printed and said and it's all turn into very untidy and filthy, and I don't wish to get into it anymore. I really respect Abhishek as a person and had one of my best experiences working in Delhi 6. Aishwarya Rai is Aishwarya Rai. I never said that. I would address her in a deferential way, but I would never call her aunty."

Sonam received flak for her comment

This controversy often resurfaces on social media. Years back, Sonam-Aishwarya's controversy went viral on Reddit. An angry user wrote, "You need to have a career for someone to destroy it." Yet another netizen commented, "So by that logic, Salman would be an uncle since he co-starred with Anil in many movies. How come she did a rom-com with Salman Uncle in Prem Ratan...?? She also worked with Abhishek in Delhi 6, who's apparently husband of Aunty Aish. She was paired with Bobby Deol in Thank you although Bobby did a romantic movie with Aunty Aish: Aur Pyaar Hogaya na, back in 1997. The list goes on and on.

Disha Parmar

Shares Adorable Glimpses From Her Day Out With Daughter Navya

isha Parmar has been enjoying the best phase of her life — motherhood. The Television actress is a doting mom to a daughter, named Navya, whom she shares with her husband and singer Rahul Vaidya. She often treats her Instafam with adorable glimpses of her baby. Recently, the Bade Achhe Lagte Hain 2 fame dropped a couple of pictures from her day out with Navya, making the fans go gaga over their bond.

Taking to Instagram, Disha posted a couple of selfies, wherein the mother-daughter duo is seen enjoying a relaxing day under the trees on a bright sunny day. In the snapshots, the actress held her daughter close, as they appeared relaxed and happy. Navya looked straight into the camera with a slight smile on her face.

Both of them kept it casual. As Disha opted for a white T-shirt paired with huge brown shades, Navya looked cute in a light green top. Sharing the pictures, she wrote in the caption, "It's

Navu's World & mumma is just living in it. #19MonthsToday."In no time, the comment section was flooded with reactions from her fans and admirers. An Instagram user wrote, "Awwdorable." Another commented, "So sweet and very cute." One of them stated, "Two Cuties in one frame."

Disha tied the knot with singer Rahul Vaidya on July 16, 2021, in Mumbai. The marriage was an intimate affair with just close friends and family members in attendance. The couple welcomed their little bundle of joy, Navya, in September 2023.On the work front, Disha is a popular face of the Television industry and has appeared in popular shows including Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara and



Woh Apna Sa. She was last seen in the TV show Bade Achhe Lagte Hain Season 3, wherein she portrayed the role of Dr Priya Sood. Backed by Ektaa Kapoor, the show also featured Nakkul Mehta, Supriya Shukla and Shrishti Jain in the lead roles

The actress took a break from acting after welcoming her daughter in 2023. She is yet to announce her next project. Rahul, on the other hand, is currently seen in Laughter Chefs: Unlimited Entertainment Season 2.

